

जगत विज्ञान



महाराष्ट्र और झारखंड में महिला वोटर रहीं असरदार



केन्द्रीय मुद्दों को
जनता ने नकारा





प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका

वर्ष 25 अंक 04 दिसम्बर 2024



महाराष्ट्र और झारखंड में महिला वोटर रहीं असरदार



केन्द्रीय मुद्दों को
जनता ने नकारा



(पृष्ठ क्र.-6)

- मुफ्त की रेवडियों ने सरकारों की कर दी वापसी23
- महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त चुनावी रणनीति ने
अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया27
- कौन होगा मध्यप्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष?29
- मध्यप्रदेश में अच्छी नहीं है अमृत सरोवर की स्थिति32
- विष्णु देव साय सरकार का एक साल34
- जहरीले कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती40
- अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर छिड़ गया है नया विवाद44
- एशियाई समाजवाद में है भारत की विदेश नीति की स्थिरता55
- छत्तीसगढ़ के पितामह थे सेठ शिवदास डागा59
- Maharashtra Assembly Elections: OBCs teach
Jarange's patron Sharad Pawar a lesson62





बांग्लादेश : हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत में आक्रोश

पिछले कुछ महिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की आस्था और जीवन को तहस नहस किया जा रहा है। जिसका आक्रोश अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पूरे भारत में आक्रोश के रूप में रैलियां आयोजित की गईं। बांग्लादेश में 77-78 वर्षों के बाद इतिहास दोहराया जा रहा है। वही चीखें, वही रूह कापता करुण वंदन, वही आंसुओं से डबडबाई आंखें, वहीं पाशवी बलात्कार के बाद पेंक्री गई बिभत्स लाशें, वही उजड़े हुए, जलते हुए घर, वही खामोश, मूकदर्शक बना स्थानीय प्रशासन और वही असहाय हिंदू। विभाजन के समय का दृश्य पूरे बांग्लादेश में पुनः प्रस्तुत हो रहा है। वैसे बांग्लादेश के लिए यह नया नहीं है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाह, जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर हिंदुओं का वंशच्छेद प्रारंभ किया था। 23 मार्च 1971 को चालू हुए इस आक्रमण में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान (अभी का बांग्लादेश) के 30 लाख हिंदुओं को मात्र कुछ ही महीनों में, पाशवी तरीके से मार दिया गया था। चार लाख से ज्यादा जवान बहू - बेटियों पर निर्मम बलात्कार किए गए थे। इन सब के बाद भी, बांग्लादेश का साहसी हिंदू, जिजीविषा के साथ डटा रहा। उसने अपने मातृभूमि को नहीं छोड़ा।

बांग्लादेश के हिंदुओं के इस अदम्य साहस से चिढ़कर, वहां के अतिवादी मुसलमानों ने 05 अगस्त 2024 से हिंदुओं के जिनोसाइड को दोहराना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ छात्रों का आंदोलन, प्रारंभ में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में था। अनेक बाहरी ताकते इस आंदोलन में शामिल थीं। किंतु जैसे ही 5 अगस्त को शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश से पलायन किया, वैसे ही यह सारा आंदोलन हिंदू-बौद्ध नागरिकों के विरोध में चला गया। तब से चार महीने होते आए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 अगस्त से आज तक, बांग्लादेश के हिंदुओं ने रात को ठीक से नींद नहीं ली है। हजारों हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है। इनमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध उद्योगपति, कलाकार, गायक, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी... सभी का समावेश है। खुलना, रंगपुर, राजशाही, बारीसाल, चिटगांव, सिल्हट.... बांग्लादेश के सभी विभागों में हिंदुओं पर हमले अभी भी हो रहे हैं। मंदिर तोड़ना, मूर्तियों को ध्वस्त करना यह तो आम बात हो गई है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, इस वर्ष दुर्गा पूजा के समय मात्र 35 दुर्गा पूजा मंडपों को अतिवादी मुसलमानों ने ध्वस्त किया। किंतु यह अत्यंत गलत आंकड़े हैं। बांग्लादेश के जातीय हिंदू महाजोट (राष्ट्रीय हिंदू गठबंधन) के अनुसार, सैकड़ों दुर्गा पूजा मंडपों को पूर्णतया ध्वस्त किया गया है। मात्र 05 अगस्त से 31 अगस्त के बीच, 49 हाई स्कूल और कॉलेज के हिंदू शिक्षकों से जबरन, बलात रूप से, अपनी नौकरी से त्यागपत्र लिए गए। चांदपुर जिले के फरीदगंज गांव के, गल्लक आदर्श डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हरिपद दास को मुस्लिम विद्यार्थियों ने अत्यंत घृणास्पद और अमानुष तरीके से अपमानित किया।

बांग्लादेश सरकार ने 5 अगस्त के बाद, एक ही महीने में 252 पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। बांग्लादेश में अब एक भी हिंदू पुलिस अधिकारी नहीं है। अकेले खुलना डिविजन का ही उदाहरण ले, तो वहां अब भी हिंदुओं पर हिंसा का तांडव चल रहा है। 5 अगस्त की रात को खुलना डिविजन के जशोर शहर के पास, बेजापारा गांव में रहने वाले, 200 हिंदू परिवारों पर जबरदस्त आक्रमण हुआ। उनके घर लूट गए। जिंदा व्यक्तियों के साथ घर जला दिए गए। महिलाओं को भगाकर ले जाया गया। पुलिस ने फोन भी नहीं उठाया। हिंदुओं पर हो रहे इस बिभत्स और नृशंस आक्रमण को, बांग्लादेश की पुलिस, मूकदर्शक बन देखती रही। 06 अगस्त को भी हिंदुओं पर आक्रमण जारी रहा। बागेरहाट सदर उपजिला में, वहां के लोकप्रिय सेवानिवृत्त स्कूल टीचर, मृणाल कांति चटर्जी को बेदर्दी से काटकर मार डाला गया। जेशोर शहर में उस दिन, 50 हिंदू घरों को लूटकर, उन्हें आग के हवाले किया गया।

विजया पाठक



महाराष्ट्र और झारखंड में महिला वोटर रहीं असरदार



केन्द्रीय मुद्दों को जनता ने नकारा



महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मेरी लाइकी बहिन योजना हो या मध्यप्रदेश की लाइली बहिन योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री मंडियां दीदी योजना हो या पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं का वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए कारगर साबित दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी-अपनी योजनाओं से महिलाओं को अपनी तरफ करना चाहती है। आने वाले समय में किसी भी पार्टी के लिए ये कितना कारगर साबित होने वाला है? यह तो आने वाला समय बतायेगा। लेकिन अब इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में महिलाएं सियासत में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। क्योंकि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं ने जिस तरह से अपनी अहमियत बताई है उससे तो यही लगता है कि वो ही सत्ता की सूत्रधार हैं। दोनों राज्यों में महिला वोटर्स को प्रमुख भूमिका में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों की जगह पर पार्टियों ने उनके हित की कई योजनाओं का वादा किया था। खासकर मुफ्त की योजनाओं को लेकर वादे किये थे। जिनका असर भी दिखा। महाराष्ट्र में महायुति को 233 सीटें मिली हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी महज 49 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी अपने दम पर 132 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) 57, एनसीपी 42, कांग्रेस 16, शिवसेना (यूटीएस) 20 और एनसीपी (शरद पवार) 10 सीटें जीती। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हो गई है। चुनावी नतीजों में INDIA ब्लॉक ने 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 15 सीट अधिक है। INDIA ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) 34, कांग्रेस 16, राजद 04 और भाकपा माले 02 सीटों पर जीता है। घुसपैठ और रोटी-बेटी-माटी के दम पर राज्य की सत्ता में वापसी का दंभ भरने वाली भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई है। जो पिछली बार यानी 2019 से 04 सीट कम है। 2019 में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं। वहीं इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ही हावी रहे। केन्द्र स्तर पर उठाये जाने वाले मुद्दे नहीं चल पाये। जनता ने उनको नकार दिया। दूसरी तरफ देखा जाये तो मोदी फैक्टर भी फेल ही रहा। झारखंड में मोदी की काफी रैलियां हुईं और घुसपैठ जैसे मुद्दों को काफी हवा दी लेकिन नहीं चल पाये। शायद यही कारण रहा कि इस बार के चुनाव में मोदी को केन्द्र में नहीं रखा गया।

विजया पाठक

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही उपचुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति को 233 सीटें मिली हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी महज 49 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी अपने दम पर

132 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) 57, एनसीपी 42, कांग्रेस 16, शिवसेना (यूटीएस) 20 और एनसीपी (शरद पवार) 10 सीटें जीती। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को 230 सीटों पर जीत

हासिल हुई है। भाजपा ने 132, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ने 57 और NCP (अजित पवार) ने 41 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला महा विकास अघाड़ी (MVA) 46 सीटों पर सिमट गया। शिवसेना (उद्धव) 20, कांग्रेस 16 और NCP (शरद पवार)

सत्ता का नया केन्द्र बिन्दु नारी शक्ति



महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नारी शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। चुनाव में महिलाओं ने बड़ चढ़ कर मतदान किया। जिसका प्रमुख कारण था महिलाओं के हित में किये गये वादे। इससे पहले भी कई राज्यों में महिलाओं से मतदान कर सरकारों का गठन किया है।

के हिस्से 10 सीटें आईं। 02 सीटें सपा ने जीती हैं। 10 सीटें अन्य के खाते में गईं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4 प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4 प्रतिशत वोट पड़े थे। इस बार 65.11 प्रतिशत वोटिंग हुई।

वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन

झारखंड में हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हो गई है। चुनावी नतीजों में INDIA ब्लॉक ने 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 15 सीट अधिक है। INDIA ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) 34, कांग्रेस 16, राजद 04 और भाकपा माले 02 सीटों पर जीता है।

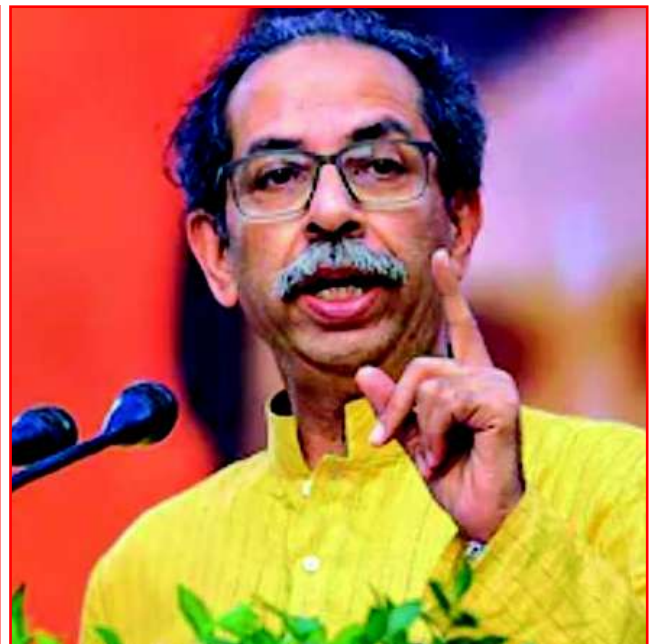
की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हो गई है। चुनावी नतीजों में INDIA ब्लॉक ने 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 15 सीट अधिक है। INDIA ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) 34, कांग्रेस 16, राजद 04 और भाकपा माले 02 सीटों पर जीता है। INDIA अपने गढ़ संथाल और कोल्हान को बचाने में कामयाब रहा है। दोनों इलाके में भाजपा ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। घुसपैठ और रोटी-बेटी-माटी के दम पर राज्य की सत्ता में वापसी का दंभ भरने वाली भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई है। जो



पिछली बार यानी 2019 से 04 सीट कम है। 2019 में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं। INDIA की जीत के पीछे कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मंडियां सम्मान योजना और कल्पना सोरेन रहीं। इसके अलावा JMM ने टिकट बांटने में सावधानी

बरती और अपने क्षेत्र में फोकस करने वाले नेताओं को तरजीह दी। विपक्ष को उसके घुसपैठ के मुद्दे में ही फंसा दिया। झारखंड में बीजेपी लगातार दो विधानसभा चुनाव (2019 और 2024) हार चुकी है। वैसे इस साल आम चुनाव के बाद जिस विधानसभा

चुनाव पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित था, वह महाराष्ट्र का चुनाव था। महाराष्ट्र न केवल उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद भेजने वाला राज्य है, बल्कि यहाँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी स्थित है। इस कारण से यह चुनाव खास था।



अब दिल्ली और बिहार की बारी



अब सभी की निगाहें दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर टिक गई हैं, जिसके जनवरी-फरवरी के बीच होने की संभावना है। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन एक बार फिर बाकी पार्टियों के लिए चिंता की बात बन गई है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन नतीजों का कितना फायदा मिलेगा? दिल्ली में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी लेकिन उनके लिए अहम होगा बिहार का चुनाव। इस बात की चर्चा अभी से है कि बिहार में गठबंधन का क्या समीकरण बनेगा, महाराष्ट्र में भाजपा की बड़ी जीत के बाद ये संकेत साफ है कि वो अपने गठबंधन साथियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस चुनाव के नतीजों के बाद अगर बीजेपी उसी अंदाज़ में दिल्ली में चुनाव लड़ेगी तो क्या कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ सकती हैं? अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी साथ आए थे लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान नहीं हुआ। वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फर्क है, इसलिए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो दोनों को फायदा ही फायदा है। जिस तरह जेएमएम ने हेमंत सोरेन को लेकर लोगों में हमदर्दी पैदा की कि किस तरह गलत मामले में उन्हें जेल भेजा गया। उसे आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से देख रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल भेजा गया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। इन मुद्दों को लेकर भी 'आप' खेलने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी को अगर ये चुनाव जीतना है तो उन्हें प्रदूषण से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का अच्छी तरह से सामना करना पड़ेगा। चूंकि विपक्ष अब हरियाणा और महाराष्ट्र भी हार गया है तो तो उनके लिए ये साफ संदेश है कि उन्हें गठबंधन के साथ काम करना पड़ेगा लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की राजनीति आम आदमी पार्टी के पूरे खिलाफ है। इस रवैये को बदलना होगा। अगर कांग्रेस और 'आप' को दिल्ली में गठबंधन करना है तो उन्हें अपने स्थानीय नेताओं को एक साथ लाना होगा जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाड़ी' के बैनर तले इंडिया

गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव

में यह स्थिति पलट गई। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़

महाराष्ट्र

महायुति के आगे बह गया महाविकास अघाड़ी



कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में महाराष्ट्र के हिस्से में 48 सीटें आती हैं। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 और महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली थीं। जिसके बाद माना जा रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, तब महाविकास अघाड़ी 288 सीटों में से 46 सीटों

पर ही सिमट गई है। बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी और महायुति के अन्य दलों ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्हें इस चुनाव में इतनी ज्यादा बढ़त मिली। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएसएस का योगदान ज्यादा था। भाजपा ने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना' के संदेश को पहुंचाने के लिए सीटों की पहचान की और हर क्षेत्र में महिला प्रभारी बनाई गईं, जिन्होंने

भाजपा को अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब सभी की निगाहें दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों पर टिक गई हैं,

जो जनवरी-फरवरी के बीच होने की संभावना है।

उद्धव ठाकरे और शरद पवार की

चुनौतियां

उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार की एनसीपी को हार का सामना



भाजपा के इस संदेश को हर महिला तक अच्छी तरह पहुंचाया। इसका फायदा ये मिला कि हर विधानसभा क्षेत्र से महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा वोट किया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे में कुछ गलतियां की थीं लेकिन इस बार उन्होंने खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में सर्वे करवाए और संगठन के जरिए वहां टिकट दिए गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिस तरह मुस्लिम वोटों में एकजुटता दिखी थी उसकी काट के लिए 'एक हैं, तो सेफ हैं' जैसे नारों को बड़े ही सधे अंदाज़ में लोगों तक पहुंचाया गया। इसका महायुति को काफी लाभ मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महायुति की जीत में आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई। महायुति की जीत में 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन' का असर

बहुत ज्यादा रहा। साथ ही युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए जो पैसे जमा हुए थे उसका भी असर हुआ है। भाजपा ने हिंदुत्व कार्ड इस बार जमकर खेला है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा खुद देवेंद्र फडणवीस भी 'वोट जिहाद' की बात कर रहे थे, जिसके कारण इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा। भाजपा ने इस चुनाव में अच्छा पोल मैनेजमेंट किया, चाहे वो उम्मीदवार को चुनना हो या आरएसएस की भूमिका हो। उसने बिल्कुल सधे अंदाज़ में इसे अंजाम दिया। ये चुनाव ऐतिहासिक हैं और इसके बाद भारत में कोई भी चुनाव पुराने तरीके से नहीं लड़ा जाएगा। 75 साल में इस बार एक ऐसा वोट बैंक उभरा है जो जाति और धर्म से अलग हटकर वोट कर रहा है, और वो हैं

करना पड़ा है। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इन दोनों के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। अगर हम शरद पवार की बात करें तो इतना कुछ

होने के बाद भी उन्होंने दस सीटें जीतीं, जिससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन

महिलाएं। इसके बाद चुनाव में उस तरह का प्रचार नहीं होगा, बस एक एजेंडा चलेगा कि कैसे महिलाओं के वोट बैंक को अपनी योजनाओं से हम साध सकते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के तीनों दल में ओवर कॉन्फिडेंस की लहर थी। लोकसभा चुनाव के बाद मिट्टी से उनका नाता टूटने लगा और पार्टियां हरियाणा की तरह हवाओं में रहने लगीं, कितनी सीटें आने वाली हैं इस चीज़ के उपर उनका ध्यान नहीं था। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों में



'ओवर कॉन्फिडेंस' आ गया था। महाराष्ट्र चुनाव में कभी अकेले दम पर 200 से ज्यादा सीटें लाने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 16 सीटों के लिए भी संघर्ष करती दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी कर रही है, लेकिन नतीजों ने फिर से कांग्रेस की राजनीति को सवालियों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पहले हरियाणा में हारी और अब महाराष्ट्र में उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार से कांग्रेस को ये समझ आ जाना चाहिए कि हाईकमान महाराष्ट्र जैसा राज्य नहीं चला सकता, जहां पर पांच बड़े क्षेत्र हैं। अगर विदर्भ क्षेत्र को देखें तो भाजपा ने कांग्रेस को लगभग पूरा हटा दिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसे हम कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) का क्षेत्र मानते थे वहां पर आज सबसे ज्यादा भाजपा के विधायक हैं। कांग्रेस

आलाकमान ने एक दो महीने पहले ऐसे प्रभारी भेजे, जिन्हें राज्य के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही यहां के स्थानीय मुद्दों के बारे में पता है। वो स्थानीय लोगों के बारे में भी कुछ नहीं जानते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस आलाकमान की भी आंख खोल दी। जिस भरोसे के साथ राहुल गांधी ने विदर्भ के प्रभारी के रूप में बघेल को जिम्मेदारी सौंपी थी बघेल राहुल के भरोसे पर एकदम उलट बैठे और पार्टी का विदर्भ से सूपड़ा साफ हो गया। वहीं भाजपा ने जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर योजना बनाई उस तरह की योजना हमें कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखी। यही वजह है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर सिमट कर रह गई।

आरएसएस की भूमिका

महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत में संघ की बड़ी भूमिका

अब उद्भव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में बहुत ही कमज़ोर विपक्ष का होना एक चिंता की बात है।

महाराष्ट्र में इस तरह अघाड़ी की रणनीति फेल

महायुति की माझी लडकी बहन योजना

के तरह गरीब महिलाओं के खाते में हर माह 1500 रूपए जमा किए जाते हैं। इसकी काट में विपक्षी एमवीए ने भी महिलाओं को



मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में कहा गया कि आरएसएस कुछ हद तक या तो नाराज़ था या बीजेपी के लिए उतना सक्रिय नहीं दिखा था। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कहा गया कि संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो ऐसे में क्या भाजपा और संघ के संबंध में ये सुधार के संकेत हैं या आरएसएस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी? 'संघ कोई भी काम करता है तो उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ता है लेकिन हां जब वो नाराज़ होते हैं तो वो और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

महाराष्ट्र: महायुति की जीत के 07 फैक्टर

■ लड़की बहिन योजना और टोल न वसूलना

भाजपा नेतृत्व महायुति सरकार ने की लड़की बहिन योजना लागू

करना सही फैसला साबित हुआ। इससे पहले मध्यप्रदेश में प्रचंड जीत का श्रेय भी वहां लागू लाडली बहना योजना को दिया गया। महाराष्ट्र की जनता ने माना कि सीएम एकनाथ शिंदे के चलते उनके बैंक खाते में हर महीने धनराशि आ रहे हैं। अगर शिंदे दोबारा सीएम बनते हैं तो ये रूपये आते रहेंगे और बढ़ भी सकते हैं। लाडकी बहिन योजना का असर यह हुआ कि एमवीए के कोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने भी महायुति को वोट दिए, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आ रहा था। चुनाव से पहले महायुति सरकार ने राज्य के कई टोल प्लाजाओं को टोल फ्री कर पुरुष मतदाताओं को अपने पक्ष में किया।

■ शिंदे को सीएम बनाकर साधा बड़ा निशाना

भाजपा का एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना और

3,000 रुपए देने का वादा किया जिस पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के बाद यह

पहला चुनाव था। शिंदे सेना और उद्धव सेना 49 सीटों पर आमने-सामने थी। अजित और और शरद की एनसीपी 38

सीटों पर भिड़ी। शिंदे की सेना और अजित की एनसीपी ही असली साबित हुई। मराठा समुदाय के लिए ओबीसी दर्जे की मांग को

लगातार बनाए रखना, एक ऐसी चाल साबित हुई, जिसने एमवीए को चारों खानों को चित कर दिया। दरअसल, शिंदे मराठा क्षत्रप हैं। उनको सीएम बना भाजपा की मराठा प्राइड को भुनाने की रणनीति कारगर साबित हुई। इतना ही नहीं, भाजपा समय-समय पर यह भी मैसेज दिया कि शिंदे फिर से सीएम बन सकते हैं। जरांगेर पाटील के मराठा आंदोलन के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन खुश थी, लेकिन भाजपा ने शिंदे पर दांव लगा, एमवीए को शिकस्त दे दी। शिवसेना (उद्धव) को कमजोर करने में शिंदे में अहम भूमिका निभाई। मराठी जनता ने शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना और ठाकरे परिवार को बाहरी।

■ भाजपा-शिवसेना का DNA एक

महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के उद्देश्य से साल 1989 में भाजपा और शिवसेना का पहली बार गठबंधन हुआ था। दोनों के बीच गठबंधन का मुख्य आधार हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो दोनों दलों को एक साथ लेकर आई। हालांकि, समय-समय पर इस रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन दोनों का कोर वोटर भी एक ही था। साल 2019 में उद्धव ठाकरे भाजपा से नाता तोड़ एमवीए में शामिल हो गए, जिससे शिवसेना के कोर वोटर में नाराजगी भी थी। इस चुनाव में जहां मतदाताओं ने भाजपा नेतृत्व महायुति को जिताया है, वहीं असली शिवसेना की मुहर भी शिवसेना-शिंदे पर लगा दी है।

■ राज्य में बंटर बांट नहीं चाहते मतदाता

महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बेशक कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव गुट) शामिल हों, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए ने आईएनडीआई गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कई और पार्टियों को भी किसी को दो तो किसी को तीन सीटें दीं, जिससे मतदाताओं को मैसेज गया कि अगर एमवीए जीतता है तो राज्य में सीएम पद और मंत्रिमंडल को रार मच सकती है। इस कारण भी मतदाताओं ने महायुति को चुना।

■ भाजपा की नई रणनीति, स्थानीय को महत्व

भाजपा ने शुरूआत से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। हाल ही हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कराया। भाजपा ने यही रणनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपनाई। स्थानीय नेताओं को चुनाव प्रचार में आगे किया। यहां सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कराई गईं।

■ हिंदू-मुस्लिम दोनों को साधने में मिली सफलता

भाजपा नेतृत्व गठबंधन महायुति ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए 'बंटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं' जैसे नारों का सहारा लिया। वहीं दूसरी ओर एनसीपी (अजित पवार) के मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन देकर यह भी मैसेज दे दिया कि वे मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। दूसरा दांव चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर चला। इसके चलते महायुति को हिंदू और मुस्लिम दोनों का भर-भर कर वोट मिला।

■ भाजपा को मिला संघ का साथ

विपक्ष मानकर चल रहा था कि अब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रिश्ते पहले से नहीं रहे हैं। इसके इतर भाजपा ने आरएसएस से आई दूरियों को खत्म किया। संघ ने भी चुनाव में भाजपा का पुरजोर साथ दिया। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर-घर लेकर गए और जनता से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा नेतृत्व महायुति गठबंधन को वोट देने की अपील की। संघ कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा सीट लेकर इस बार वोटिंग करें। लोगों को देश में भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी जागरूक किया।

लेकर चले आंदोलन ने लोकसभा चुनावों में महायुति उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इस बार संघ-संगठन की सक्रियता ने

अघाड़ी को इसका फायदा नहीं उठाने दिया। झारखंड में आदिवासी इंडिया गठबंधन के साथ

झारखंड में एक तिहाई से ज्यादा (28) एसटी सीटें हैं। आबादी का 26 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी है। 21 में आदिवासियों

झारखंड

बीजेपी का नहीं चला बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा



एक ओर जहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी मज़बूत नज़र आई वहीं दूसरी ओर झारखंड में उसे संघर्ष करना पड़ा। यहां 81 सीटों में से बीजेपी 21 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। झारखंड में बीजेपी ने काफी हद तक नकारात्मक अभियान किया, जिसमें घुसपैठियों जैसे मामले शामिल हैं। अगर जेएमएम और कांग्रेस के चुनाव अभियान को देखें तो वो सकारात्मक तरीके से अपने काम के बारे में बात कर रहे थे, जिसका फायदा उन्हें मिला। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब संघ ने

इस बात पर नाराज़गी जताई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के रूझानों में हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ गए हैं। 81 सीटों में झामुमो गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है यानी बहुमत के आंकड़े से 13 सीट कम। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में INDIA ब्लॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सोरेन ने जनता का धन्यवाद जताया और कहा कि जमीन पर मौजूद उन नेताओं का

आबादी कम से कम एक लाख है। इन सीटों पर झामुमो की अच्छी पकड़ है। भाजपा इसे तोड़ने में सफल नहीं रही। हेमंत सोरेन की

पत्नी कल्पना सोरेन के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट था। सोरेन परिवार से चार मैदान में थे। हेमंत, कल्पना व भाई बसंत

जीतने में सफल रहे। भाभी सीता सोरेन (भाजपा) हार गईं। हेमंत ने जीत का श्रेय कल्पना को दिया है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा



भी शुक्रिया, जो जनता की ताकत को पार्टी तक लेकर आए। रांची की सड़कों पर अब पोस्टर लग रहे हैं। सबके दिलों पर छा गया, शेरदिल सोरेन फिर आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर CM की कुर्सी संभाली। झारखंड के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूँ। विपक्ष में रहकर हम राज्य के विकास और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर काम करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद झारखंड में 8 एगिजट पोल आए। इनमें से 4 में भाजपा गठबंधन, जबकि 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। बाकी 2 एगिजट पोलस ने हंग असेंबली के आसार जताए थे।

वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तरह से पांच साल बाद

सत्ता वापसी के लिए मेहनत की, उसका सार्थक परिणाम नहीं मिल पाया। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी और भाकपा-माले को गठबंधन को वर्ष 2024 के चुनाव में जबर्दस्त सफलता मिली। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी, आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा-आर को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चुनाव परिणाम में कुल 81 सीटों में से 56 सीटें जीतकर हेमंत सोरेन ने बीजेपी के विजय रथ को झारखंड में रोक दिया। झारखंड के छह क्षेत्र कोल्हान, संताल, कोयला, पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर में से पांच में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। चुनाव परिणाम के अनुसार जेएमएम लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। पार्टी ने 43 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें 34 पर जीत मिली। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस 30 सीट पर लड़ी और 16 सीटें मिली।

की पत्नी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा हार गई हैं। चंपई सोरेन जीतने में सफल रहे लेकिन, उनके बेटे बाबूलाल

सोरेन हार गए। रघुबर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने कांग्रेस के अजय कुमार को हरा दिया।

आदिवासी अस्मिता का मुद्दा
बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, आबादी में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए उसे

आरजेडी ने 06 प्रत्याशी उतारे और चार सीटें कब्जे में की। भाकपा-माले ने चार सीटों पर लड़कर दो सीटें फतह की हैं। वहीं एनडीए को 24 सीटें हासिल हो सकी।

झारखंड: जेएमएम की जीत के 05 कारण

■ मंडियां ने हेमंत की बचाई नैया

राज्य की 81 में से 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर पुरुष से अधिक हैं। यही कारण है कि चुनाव में INDIA की मंडियां दीदी योजना की काट में भाजपा ने गोगी दीदी योजना लाने का वादा किया। मंडियां में महिलाओं को हर माह 2500 रुपये तथा गोगी दीदी में 2100 रुपये देने का वादा है। यहां INDIA को सत्ता में रहने का फायदा मिला, क्योंकि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले 1000 रूपए जारी कर दिया और चुनाव बाद 2500 करने का ऐलान कर दिया। इस पर महिलाओं ने ज्यादा भरोसा जताया। 29 महिला बहुल सीटों में से INDIA 28 सीटों पर जीता है।

■ कल्पना सोरेन का काट नहीं खोज पाई भाजपा

पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में आई कल्पना सोरेन ने अपने भाषण और पब्लिक कनेक्ट के तरीकों से लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। INDIA ब्लॉक के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा डिमांड कल्पना सोरेन की ही रही। उनकी सधी हुई भाषा और सहज, सरल अंदाज ने लोगों को जोड़ा। कल्पना ने 100 से अधिक जनसभा की। उन्होंने सिर्फ

जेएमएम उम्मीदवारों के लिए ही चुनावी सभा नहीं की, बल्कि कांग्रेस-आरजेडी और भाकपा-माले के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगा। वहीं, भाजपा को महिला नेता की कमी खली। लोगों के अंदर कल्पना के प्रति रूझान के कारण ही भाजपा उन पर सीधा हमला करने से बचती रही।



■ हेमंत ने जेल यात्रा से सहानुभूति बटोरी

पूरे चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन भाजपा को आदिवासी विरोधी बताने पर अड़े रहे। उन्होंने हर सभा में कहा कि आदिवासियों के उत्थान से भाजपा के लोग बैचन हैं। उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर मुझे जेल भेजा। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। हेमंत ने

आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। 'रोटी, बेटी व माटी' का नारा दिया। बीजेपी ने संधाल परगना इलाके में कहा था

कि बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए कहा था कि घुसपैठिए उनकी रोटी यानी रोजगार, उनकी बेटियों से शादी कर बेटी और उनकी जमीन

यानी माटी छिन रहे हैं, लेकिन आदिवासियों ने उनके इस नैरेटिव का नकार दिया। हालांकि, बीजेपी ने कोलहान के टाइगर कहे

मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की बातें कहकर लोगों से सहानुभूति बटोरी। इसका रिजल्ट पर खासा असर दिखा।

■ भाजपा से नाराज आदिवासी वापस नहीं लौटे

रघुवर दास की सरकार में 2016 में सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश करना भाजपा को अब तक भारी पड़ रहा है। बदलाव के घाव से भड़के आदिवासी अब तक भाजपा से नहीं जुड़ पाए हैं। सीटों के आंकड़े भी बता रहे हैं। 2014 तक कुछ आदिवासी भाजपा को वोट

सकता था। उनका कहना था कि उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने को लेकर ऐसा किया, लेकिन आदिवासियों के बीच ये मैसेज गया कि बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। वो जब चाहे हम से जमीन ले सकते हैं। भारी विरोध के बाद बदलाव के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था।

■ भाजपा को उसके मुद्दे में ही उलझाया

भाजपा ने पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। पीएम से लेकर लोकल नेता तक के हर भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ

का मुद्दा हावी रहा। इसके उलट हेमंत सोरेन और INDIA ब्लॉक के नेता ये कहते रहे कि सीमा की सुरक्षा तो केंद्र के जिम्मे है, इसमें राज्य का क्या लेना-देना। साथ ही झामुमो-कांग्रेस एरिया वाइज मुद्दों को पकड़े रही।

हर एरिया में अलग-अलग मुद्दे पर बातें करती रही। जबकि, भाजपा पूरे राज्य में घुसपैठ के नाम पर चुनाव लड़ती



देते रहे हैं, इस कारण उस समय आदिवासी रिजर्व सीट पर पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक था। लेकिन रघुवर दास की सरकार ने सीएनटी एक्ट में बदलाव कर दिया। इस पर आदिवासी नाराज हो गए और भाजपा का साथ छोड़ दिया। सीएनटी एक्ट की धारा 46 में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत आदिवासियों की जमीन के नेचर को बदला जा

रही। हकीकत ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ संथाल तक सीमित है। वो भी पूरे संथाल में नहीं। भाजपा के अक्रामक रूख से बाकी वोटर एकजुट हो गए। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ पिछले 05 साल में बीजेपी ने जो कैंपेन चलाया, वो फुस्स साबित हुआ।

जाने वाले संथाल नेता चंपई सोरेन और सीता सोरेन को अपने खेमे में लाकर आदिवासियों को एक संदेश देने की

कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी की रघुवर दास सरकार के समय में आदिवासियों से जुड़े कानून को लेकर आदिवासी तबके में

मौजूद डर-आशंका ने उन्हें बीजेपी पर भरोसा करने से कहीं न कहीं रोका। वहीं, बीजेपी ने संथाल परगना को अलग करने

उपचुनावों में रहे मिलेजुले परिणाम

14 राज्यों की 46 विधानसभा और 02 लोकसभा (वायनाड, नांदेड़) सीटों के परिणाम भी आ चुके हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने CPI के सत्यन मोकेरी को 04 लाख 10 हजार वोटों से हराया। भाजपा की नव्या हरिदास (01 लाख 9 हजार वोट) तीसरे नंबर पर रहीं। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के 05 साल पुराने जीत का रिकार्ड नहीं तोड़ पाईं। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में CPI



(M) के पीपी सुनीर को 04 लाख 31 हजार वोटों के अंतर से हराया था। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रवीन्द्र वसंत राव चव्हाण ने भाजपा के संतुक हंबार्डे को 1457 वोट से हराया। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। वहीं, उत्तर प्रदेश की 09 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 07 और सपा को 02 सीटों पर जीत मिली है। 46 सीटों पर भाजपा गठबंधन 24, कांग्रेस 7, TMC 6, सपा 3, AAP 3, CPI-M, नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और भारत आदिवासी पार्टी 01-01 सीटों पर जीती। भाजपा गठबंधन में जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM), असम गण परिषद (AGP), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी (UPP) और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) शामिल हैं। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं।

का शिगूफा भी छोड़ा, जिसे आदिवासी तबके ने नकार दिया। आदिवासियों द्वारा बीजेपी को नकारे जाने का ही असर था कि आदिवासी बहुल कोल्हान-संथाल दोनों ही इलाके में बीजेपी को करारी हार देखनी पड़ी। राज्य की आदिवासियों के आरक्षित 28 सीटों में से 27 सीटों पर INDIA गठबंधन जीता।

बीजेपी का हर वार खाली

झारखंड में बीजेपी के ज्यादातर वार खाली गए। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी में बदलाव का मुद्दा, कंटेंगे तो बंटेंगे का मुद्दा- इससे पार्टी को नुकसान हुआ। भले ही इस कोशिश में हिंदुओं में ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन उसके सामने आदिवासियों और मुस्लिम ने जिस तरह साथ वोट किया, उसने रणनीति को फेल कर दिया। हालांकि, बीजेपी ने यहां बड़े पैमाने

पर अपने नेताओं को उतारा। योगी से लेकर हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति, उनके बनाए आक्रामक नैरेटिव ने झारखंड की सरल जनता को अपने भीतर सिमटने और चुपचाप अपना फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। इसी का नतीजा था कि संथाल परगना में 18 सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक सीट निकाल पाई। कभी बीजेपी का मजबूत

वहीं, भाजपा की 11 सीटों समेत NDA के पास कुल 17 सीटें थीं। इस तरह से भाजपा गठबंधन को कुल 07 सीटों का फायदा है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी नौ में से सात सीटें जीत गई तो ऐसे में इन नतीजों को योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे चुनाव में एजेंडा तैयार किया, उन्होंने



'बंटेंगे तो कटेंगे' का जो नारा दिया, उससे उनके कोर वोटर पर प्रभाव पड़ा और विपक्ष सिर्फ इन्हीं नारों के उपर बात करता रहा। जो भी योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठ रहे थे शायद इस चुनाव में उन्होंने सबको चुप करा दिया। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरीं और चार लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ज़मीन और उसकी नब्ब को पकड़ने और उस पर अपनी राय रखने के मामले में जो

महारत जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिरोज़ गांधी की थी, वहां से लेकर मौजूदा समय तक कांग्रेस के लिए काफी कुछ बदला है। जिस तरह की स्थिति हम आज देख रहे हैं उसमें आने वाले समय में प्रियंका गांधी का 'लड़की हूँ लड़ सकती हूँ' का नारा बेहद प्रभावशाली साबित होगा। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव और महूआ मोइत्रा के बाद प्रियंका गांधी एक मज़बूत स्पीकर के रूप में सामने आ गई हैं, यही कारण है कि संसद में दोनों ही पक्षों में और भी ज्यादा टकराव देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी जानती हैं कि कैसे मुद्दों को रखा जाए, कैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर किया जाए।

किला रहे कोल्हान में भी शहरी सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी को खास सफलता नहीं मिली।

महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां महायुक्ति ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपना दम दिखा दिया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले चार पार्टियों के गठबंधन ने कुल

56 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बराबरी का रहा। दो उपचुनाव में बुधनी बीजेपी ने जीता और विजयपुर कांग्रेस ने। एक हिसाब से देखा जाये तो यहां पर बीजेपी की हार ही हुई है। क्योंकि जिस बुधनी को बीजेपी लाखों वोटों से जीतती आ रही है वह केवल हजारों पर सिमट गई है। इन चुनाव परिणाम से भारत के राजनैतिक स्वरूप पर

कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की स्थिरता में भी कोई अंतर नहीं होगा लेकिन इन चुनाव परिणामों भविष्य के लिये एक बड़ा संकेत दिया है। इस चुनाव में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन, धर्मगुरु और छद्म सेकुलरों ने पूरी योजना से काम किया। पहले लोकसभा चुनाव प्रचार में जातीय जनगणना का शोर किया गया। गाजियाबाद के छद्म सेकुलर



पत्रकार अभी खुलकर सक्रिय थे वे लोकसभा चुनाव प्रचार में जातीय समीकरणों को तूल दे रहे थे। तब न केवल उम्मीदवार की जाति से मतदाताओं के जाति आधारित आँकड़े देकर सामाजिक रेखाएँ खींची जा रहीं थीं अपितु व्यक्तिगत अपराध की घटनाओं को भी जाति से जोड़कर सनसनीखेज बनाने का प्रयास हुआ था जो अभी भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम में इस जाति आधारित धुँध का प्रभाव देखा गया। सनातन समाज को जाति आधारित गणना में उलझाकर अब मुस्लिम समुदाय को संगठित और आक्रामक बनाने का प्रयास हुआ। यह ठीक वैसा ही है जैसे 1921 के बाद भारतीय समाज जीवन में देखा गया। इतिहास गवाह है कि मालाबार हिन्सा के बाद जातीय गणित, मुस्लिम कट्टरता बढ़ी थी। वहीं कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राह पकड़ी थी जो अभी भी यथावत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुस्लिम समुदाय को आक्रामक बनाने का प्रयोग किया जाने लगा था। इसे हम कांवड़ यात्राओं पर पथराव, गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव पर हुये हमलों से समझा जा सकता

इन चुनाव परिणाम में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के मतदाताओं में जागरूकता का संदेश है तो यह संकेत भी है कि भारत की विकास गति को अवरूद्ध करने वाली शक्तियाँ अथवा केवल तुष्टीकरण और हिन्दु मुस्लिम की राजनीति करके अपना स्वार्थ पूरा करने वाले तत्त्व भी चुप नहीं बैठेंगे। वे कोई नया कुचक्र करेंगे।

है। विधानसभा के इन चुनाव परिणामों में दोनों प्रकार की झलक है। एक तो सनातन समाज में जागरूकता देखी जा रही है और दूसरे कम प्रतिशत ही सही लेकिन मुस्लिम समाज में भी जागरूकता बढ़ी है। मुस्लिम समाज का प्रबुद्ध वर्ग कट्टरवाद की राजनीति का मर्म समझने लगा है इसीलिये आक्रामक प्रचार के बाद भी भाजपा गठबंधन

उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट मिले। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर यह जागरूकता स्पष्ट देखने को मिल रही है। इन चुनाव परिणाम में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के मतदाताओं में जागरूकता का संदेश है तो यह संकेत भी है कि भारत की विकास गति को अवरूद्ध करने वाली शक्तियाँ अथवा केवल तुष्टीकरण और हिन्दु मुस्लिम की राजनीति करके अपना स्वार्थ पूरा करने वाले तत्त्व भी चुप नहीं बैठेंगे। वे कोई नया कुचक्र करेंगे। इस चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नायडू को तोड़ने का प्रयास किया, ऐसे प्रयास और बढ़ सकते हैं। इसलिए समाज और सरकार दोनों के अतिरिक्त राजनैतिक दलों को भी चुनाव में तुष्टीकरण का खेल करने की बजाय राष्ट्र विकास के विन्दु सामने रखकर चुनाव तैयारी करनी होगी। तभी 2047 तक भारत के सर्वोन्नत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होने का लक्ष्य पूरा होगा।

महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव....

मुफ्त की रेवड़ियों ने सरकारों की कर दी वापसी



देश के मतदाता लगता है, मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में मतदान करने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ताएं बरकरार रही हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन वाले महायुति ने विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 55 सीटें जीतकर भाजपा को बहुत पीछे धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल करके जता दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जनता सम्मान के साथ स्वीकार रही है। लेकिन भाजपा को मध्यप्रदेश में बड़ा झटका लगा है।

प्रमोद भार्गव

देश के मतदाता लगता है, मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में मतदान करने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ताएं बरकरार रही हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन वाले महायुति ने विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने

55 सीटें जीतकर भाजपा को बहुत पीछे धकेल दिया है। उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल करके जता दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जनता सम्मान के साथ स्वीकार रही है। लेकिन भाजपा को मध्यप्रदेश में बड़ा झटका लगा है। विधानसभा विजयपुर में दल-बदलकर आए भाजपा प्रत्याशी और राज्य सरकार में

वन मंत्री रामनिवास रावत को मतदाता ने नकार दिया है। अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भी भाजपा का अच्छा प्रदर्शन देखने में आया है।

उप्र के बाद महाराष्ट्र विधानसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। पिछले तीन दशक में यहां किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। अतएव गठबंधन सरकारें ही

महाराष्ट्र : लड़की बहिन योजना



सरकार चलाती रही हैं। इसी कारण यहां सरकारें गिराने के लिए विधायकों की तोड़-फोड़ भी देखने में आती रही हैं। शिवसेना से टूटकर भाजपा में शामिल हुए एकनाथ शिंदे भाजपा की दम पर मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने चाचा शरद पवार को झटका देकर अजीत पवार ने एनसीपी (अजीत पवार) बनाई और वे महायुति का हिस्सा बन भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हिस्सा बन गए। अब यही महायुति नई सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ शरद पवार के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी पार्टी थी, जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी। लेकिन महायुति से करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां चुनाव इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच था। भाजपा को छोड़ किसी भी दल ने कुल 288

सीटों की आधी से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए तय था कि किसी एक दल की सरकार महाराष्ट्र में 30 वर्ष बाद भी बन गई। भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन बिना सहयोगियों के वह भी सरकार नहीं बना

**महाराष्ट्र में इंडिया
गठबंधन को लगा बड़ा
झटका, लोकसभा के
परिणामों को नहीं भुना
सका इंडिया गठबंधन।**

पायी। हालांकि भाजपा 132 सीटें जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। अतएव एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद देवेन्द्र फडणवीस के लिए पद छोड़ना पड़ा। राज्य के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार से ही मात खाकर हाथ मलते रह गए। इधर बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। वे अपने पिता बाल ठाकरे की विरासत को बचाने में असफल रहे हैं।

महाविकास अघाड़ी को जीत की इसलिए उम्मीद थी कि क्योंकि इस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 48 में से 30 सीटें जीत ली थीं। इस कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन सत्ता परिवर्तन को लेकर आशांवि्त था। परिणाम से तो तय हो ही गया है कि महाविकास अघाड़ी की आशाओं पर पानी फिर गया है, इससे पहले एग्जिट पोल ने भी जता दिया था

झारखण्ड : मंडियां दीदी योजना



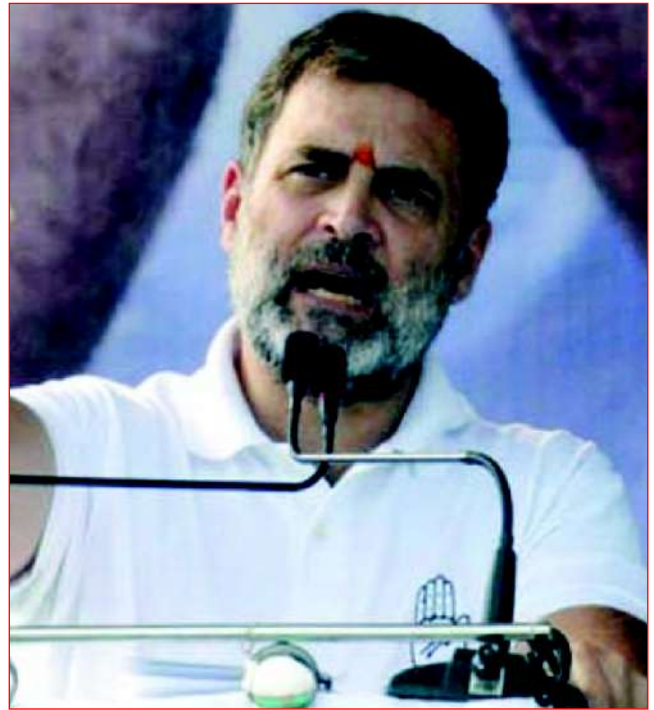
कि उसका जीतना मुश्किल है। दरअसल महाविकास अघाड़ी को यह झटका रिश्तों का रंग, बदरंग हो जाने के कारण भी लगा है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से रिश्ते तोड़कर जता दिया था कि उनके नेतृत्व को बड़ी चुनौती मिल गई है और शरद पवार अपने राजनीतिक वजूद को पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे। परिणाम के बाद इस तथ्य की पुष्टि हो गई। शरद पवार अब महाराष्ट्र के ताकतवर मराठा नहीं रह गए हैं। अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंदों का धोखा खाने के बाद 26 साल पहले उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पर है। मूलतः कांग्रेसी और पसंद से वंशवादी पवार इस उम्मीद में प्रभावी उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर पाए कि कहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले पिछड़ न जाए? उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका इसलिए लगा है, क्योंकि वे अपने पिता बाल ठाकरे की तरह प्रखर हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखने में असफल रहे। वे और उनके पुत्र आदित्य

ठाकरे उन फतवों को भी नहीं नकार पाएं, जिनमें कहा गया था कि भाजपा को वोट देने वालों का हुक्का-पानी बंद कर देंगे। एक मौलवी ने तो यहां तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं रही है। मतलब उसमें इतने बदलाव हो गए हैं कि वह मुल्ले-मौलवियों

**झारखंड में भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल में भेजना महंगा पड़ा है।
यहां घुसपैठ और ईसाईकरण के मुद्दे भी काम नहीं आए। दरअसल भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, जो वहां के आदिवासियों को लुभा सके?**

की पार्टी बन गई है। उद्धव ठाकरे ने तो मौलवियों की इस कट्टर और खतरनाक मंसूबे का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने मौलवियों को उत्तर देकर मतदाताओं का मत हासिल कर लिया। उद्धव अपनी हिंदुत्व की छवि को भविष्य में बहाल कर पाएंगे ऐसा अब लगता नहीं है।

झारखंड में भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल में भेजना महंगा पड़ा है। यहां घुसपैठ और ईसाईकरण के मुद्दे भी काम नहीं आए। दरअसल भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, जो वहां के आदिवासियों को लुभा सके? भाजपा गठबंधन को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का आदिवासी होना, भाजपा के लिए वोट बटोर लेगा, किंतु धरातल पर ऐसा दिखाई नहीं दिया। सत्ताधारी दल की जनगणना पत्रक में अलग से धर्म का कॉलम बनाने की मांग ने हिंदुत्व के मुद्दे को फीका करने का काम किया है। भाजपा के पास झारखंड में कोई ऐसा



स्वीकारने लायक चेहरा नहीं था, जिसे चुनावी कमान सौंपी जा सके? इसलिए उसने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया। वे जितना कर सकते थे, उतना किया भी। लेकिन परिणाम शून्य रहा। दरअसल भाजपा ने यहां बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ के चलते सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय घनत्व बिगड़ने की बात उठाई, परंतु यह मुद्दा समूचे झारखंड का मुद्दा नहीं बन पाया। दरअसल संथाल और उसके निकट के जिलों में घुसपैठ का प्रभाव है। परंतु उसका असर पूरे झारखंड में दिखाई नहीं देता। इसलिए भाजपा की हिंदुत्व और घुसपैठ के मुद्दे मतदाता में गहरी पैठ नहीं बना पाए।

सोनिया गांधी पुत्रमोह के चलते पुत्री प्रियंका वाड्ढा को उम्मीदवार बनाने से बचती रही हैं। लेकिन अब 52 वर्ष की प्रियंका को वायनाड के उपचुनाव में उतारा गया। यह सीट राहुल गांधी ने जीती थी, जो उन्हें खाली करनी पड़ी। क्योंकि वे रायबरेली से भी

चुनाव लड़े और जीते थे। अतएव उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना पड़ा। प्रियंका ने यह पहला चुनाव 4 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत लिया। अब एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद में होंगे। लोकतंत्र के लिए यह सुखद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवादी राजनीति के मुखर विरोधी रहे हैं। लेकिन प्रियंका ने जीत हासिल करके परिवारवादी राजनीति को कांग्रेस में मजबूत कर दिया है।

मध्यप्रदेश में रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक रहते हुए भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रावत के विधायक रहते हुए भाजपा में इसलिए लाए थे, जिससे मुरैना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर चुनाव जीत जाएं। तोमर तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन स्वयं के लाभ के लिए दल-बदल करने वाले नेता को मतदाता ने चारों खाने चित्त कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी रावत की हार बड़ा झटका है।

उन्हें सिर-मुड़ाते ही ओले पड़ने की कहावत का सामना करना पड़ा है। उनके कार्यकाल में यह पहला उपचुनाव था, जिसमें शासन-प्रशासन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा। रावत पहली बार चुनाव लड़े थे। इसके पहले वे कांग्रेस से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने हराकर जता दिया है कि जनता दल-बदलुओं के पक्ष में नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं चाहते थे कि दलबदलू उनकी छाती पर बैठकर दाल दलें। बुधनी सीट भी भाजपा इसलिए जीत पाई, क्योंकि वहां गृहनगर होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख का सवाल था। मतदाता ने उनकी लाज रखी और बाहरी प्रत्याशी होने के बावजूद रमाशंकर भार्गव को चुनाव जिता दिया। बहरहाल भाजपा ने एक बार फिर जता दिया है कि मतदाता में उसकी पैठ बनी रहेगी।

महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त चुनावी रणनीति ने अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया

भारत की खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली व बुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं की निर्णय क्षमता पर दुनियाँ हैरान

किशन भावनानी

वैश्विक स्तर पर सारी दुनियाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनावी महापर्व को हैरत भरी नजरों से देखती है कि, उनके पूरे देश के नागरिकों या जनसंख्या वाला तो भारत में एक ही राज्य है, ऐसे 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कितना बड़ा चुनावी महापर्व होता होगा, आज हम इस विषय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र व झारखंड राज्यों व अनेक राज्यों के उपचुनाव परिणामों का ऐलान हुआ, जिसके लिए मैंने तीन सटीक विश्लेषण दिए थे, तीनों विश्लेषण हंड्रेड परसेंट सटीक साबित हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यानी 288 में से 132 सीटें, शिवसेना 57 व एनसीपी को 41 सीटें मिली है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। चूँकि भारत की खूबसूरत लोकतंत्र प्रणाली व बुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं पर दुनियाँ हैरान है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त चुनावी रणनीति ने, अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया।

बात अगर हम 23 जुलाई 2024 को आए महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों की करें तो, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है, राज्य में एक बार फिर उसकी सरकार बन गई है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति को 230 से ज्यादा सीट मिली, वहीं एमवीए को



47 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में बंपर जीत पर आयोजित आभार कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी जीत है, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा की लीडरशिप में किसी गठबंधन को महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया है, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र की गुल्थी महायुति ने सुलझा ली और बंपर जीत के साथ वापसी की है। महायुति का हिस्सा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73 परसेंट तक पहुंचा दिया। महायुति का मुकाबला महा विकास अघाड़ी से था। इस

गठबंधन की मुख्य पार्टियां कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं। महाविकास अघाड़ी की कोई भी पार्टी सही प्रदर्शन नहीं कर पाई और महा विकास अघाड़ी का स्ट्राइक रेट करीब 17 परसेंट के आसपास रहा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88 परसेंट के आसपास है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर लड़ी थी और इनका स्ट्राइक रेट भी करीब 69 परसेंट रहा। अजीत पवार की एनसीपी 66 सीटों पर लड़ी थी और स्ट्राइक रेट करीब 63 परसेंट रहा। महायुति की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वह इसे लेकर थी कि अजीत पवार की पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी और क्या वह अपना वोट

बीजेपी को ट्रांसफर कर पाएगी। नतीजों से लगता है कि वोट ट्रांसफर हुआ है। अजीत पवार की इस चुनाव में मजबूत बनकर उभरे हैं। एकनाथ शिंदे की इमेज का भी महायुति को भी बहुत फायदा पहुंचा।

अगर हम महाराष्ट्र के 5 माह पूर्व लोकसभा चुनाव में आए खराब प्रदर्शन को बड़ी ऐतिहासिक जीत में पलटाने की रणनीति की बात करें तो, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान 48 में सिर्फ 18 सीटें पाने वाली भाजपा नीत महायुति गठबंधन ने छह महीने में ही बाजी पलट दी। अचूक रणनीति और सफल चुनाव प्रबंधन से अबकी बार 200 पार का नारा सफल हुआ और महायुति की महाविजय हुई। महायुति ने छह माह में बाजी पलटने पर संगठन और सरकार के स्तर पर एक साथ और कारगर प्रयास किए जिसका नतीजा रिकॉर्ड तोड़ जीत के रूप में सामने आया। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित विपक्ष का माहौल बदलने के लिए उसका नैरेटिव तोड़ना बड़ी चुनौती थी लेकिन महायुति इसमें सफल रही भाजपा नेतृत्व ने 10 हजार आम कार्यकर्ताओं से परिचियों के जरिए 5 से 6 सुझाव मांगे थे। हर जिले के कार्यकर्ताओं से पार्टी ने फीडबैक लेकर समय रहते कमियां दूर कीं। खास बात है कि भाजपा ने हर विधानसभा में गठबंधन के तीनों दलों के नेताओं की कॉर्डिनेशन कमेटियां बनाईं। जिससे तालमेल का संकट खड़ा नहीं हुआ। महिला मतदाताओं को साधने के लिए चलाई गई लाडकी बहिन योजना सफल रही। चुनाव से पहले तक ढाई करोड़ महिलाओं के खाते में तीन बार 1500-1500 रुपये भेजकर महायुति सरकार ने विश्वसनीयता हासिल की। उसे इसका लाभ मिला। टोल टैक्स हटाने, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने और प्याज एक्सपोर्ट से जुड़ी शर्तें हटाने, ऋणा माफी आदि एलानों से महायुति सरकार किसानों और मध्यवर्गीय मतदाताओं को भी साधने में सफल रही।



यही वजह रहा कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष के संविधान खतरे में नैरेटिव के कारण दलित और बौद्ध मतदाताओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस नेतृत्व महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ था। ऐसे में भाजपा ने नतीजों के तुरंत बाद दलित और ओबीसी वर्ग की 350 प्रमुख जातियों के नेताओं से मीटिंग शुरू की। दलित बहुल इलाकों में भाजपा ने संविधान यात्राएं निकालीं। गृहमंत्री के निर्देशन में चुनाव प्रभारी ने 03 महीने तक लगातार अलग-अलग जातियों के नेताओं के साथ बैठकें कर उन्हें पार्टी के साथ लाने में सफल रहे और जिसके जरिए वंचित समाज में संविधान और आरक्षण को लेकर पैन्ने ब्रह्म को पाटने में सराहनीय सफल रहे।

महाविकास अघाड़ी की असफलता के कारणों की करें तो, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने जो प्रदर्शन किया था, उसका फायदा यह गठबंधन नहीं ले पाया। यह न तो सत्ताधारी गठबंधन को महों पर घेर पाया न ही उनके नैरेटिव के जवाब में कोई काउंटर नैरेटिव सेट कर पाया। शिवसेना में बगावत के बाद जब राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी थी और शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी को उद्ध ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति थी जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने में असफल रहा। महंगाई और

बेरोजगारी जैसे मुद्दे इन्होंने उठाए लेकिन उसे लेकर माहौल नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा आक्रामकता से जातिगत जनगणना और संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाने के मुद्दे से माहौल बनाया गया था। भाजपा इस नैरेटिव को तोड़ने में लगी थी लेकिन अति आत्मविश्वास में डूबे एमवीए नेता इसका जवाब नहीं तलाश पाए। उन्होंने भाजपा बंटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों का माकूल जवाब भी समय पर नहीं दिया गया। ऐसे में यह नारे लोगों को लुभा गए। कांग्रेस की गारंटियों जैसे पुराने वादे भी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाए साथ ही तालमेल में कमी और शिवसेना से वैचारिक भिन्नता भी कहीं न कहीं नुकसानदेह साबित हुई। कुर्सी की खींचतान दर असल, लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने एकजुटता से चुनाव लड़ते हुए महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीती। इस दौरान करीब 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक की बढ़त रही। अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र में महायुति को ज़बरदस्त चुनावी रणनीति ने अभूतपूर्व जीत का इतिहास रचाया। कार्यकर्ताओं से परिचियों में फीडबैक, लाडली बहिन योजना व दो नारों ने जबर्दस्त जीत का तोहफा दिया। भारत की खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली बुद्धिजीवी सटीक मतदाताओं की निर्णय क्षमता पर दुनियाँ हैरान है।

कौन होगा मध्यप्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? वीडी शर्मा या कोई और?



विजया पाठक

मध्यप्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अब पार्टी किससे मध्यप्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? ये वो सवाल हैं जो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासे चर्चाओं में हैं। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष जब मध्यप्रदेश आए तो ग्वालियर में उन्होंने इस ओर इशारा भी किया कि अब एमपी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। उनके इस इशारे के बाद से तो कयासों का दौर भी चल उठा और दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं। मध्यप्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम आ

जगत विजन

**वर्तमान अध्यक्ष
ने बीजेपी को
बुलंदियों पर
पहुंचाया**

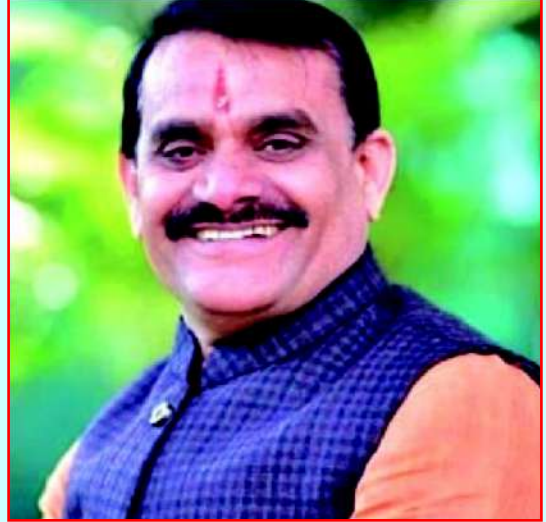
गये हैं और इसके बाद बीजेपी संगठन में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी माह या फिर नए साल में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। नए प्रदेश अध्यक्ष के फिलहाल कई

दावेदारों के नामों की चर्चाएं हैं जिनमें ब्राह्मण, ओबीसी और अनुसूचित जाति से आने वाले नेता शामिल हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि मोदी-शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री के नाम की ही तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चौंका सकती है। मध्यप्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए अलग-अलग स्तर पर चयन समिति का गठन कर कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग-अलग दलों के नेता अलग-अलग नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष के सुझा रहे

भोपाल, दिसम्बर-2024

वीडी शर्मा हैं सशक्त दावेदार

खजुराहो सांसद और वर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनने के सशक्त दावेदार हैं। वीडी शर्मा के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में भाजपा की अपार सफलता है जिसमें 2023 विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के साथ ही 2024 लोकसभा चुनावों में पहली बार 29 में से 29 सीट पर ऐतिहासिक जीत शामिल है। सदस्यता अभियान में भी मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी रहा। वीडी शर्मा की काबिलियत और राजनीतिक समझ की तारीफ बीएल संतोष, जेपी नड्डा भी कर चुके हैं। अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो भले ही वीडी शर्मा के शुरूआती कार्यकाल में कार्यशैली को लेकर खींचतान हुई हो लेकिन समय के साथ वीडी शर्मा ने पार्टी को संभाला और सभी नेताओं को एकजुट कर आगे बढ़े। यही कारण है कि आज भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सशक्त पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वीडी शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया कर



दिया था। उनका कार्यकाल अव्वल दर्जे का रहा। बीजेपी में शामिल कराने और लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर सदस्यता का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के जानकारों के मुताबिक पार्टी के वर्तमान प्रदेश मुखिया वीडी शर्मा को एक कार्यकाल और मिल सकता है। चूंकि उनके पहले कार्यकाल की अवधि बढ़ाई गई थी, इस प्रकार तकनीकी रूप से अभी उनका एक कार्यकाल पूरा होना ही माना जाएगा। पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी नेता को दो कार्यकाल पूरे करने का मौका मिल सकता है। इस लिहाज से वीडी शर्मा को अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल और मिल सकता है।

साल 2020 में बने थे प्रदेश अध्यक्ष

लगभग 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। 15 फरवरी 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने औपचारिक पत्र जारी कर वीडी शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की थी। करीब 32 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने शुरूआत एबीवीपी से की थी। चंबल क्षेत्र में भाजपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं।

क्या है बीजेपी का क्षेत्रीय समीकरण ?

मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। वह खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद हैं। वीडी शर्मा भले ही सांसद खजुराहो से हों लेकिन वह मूल रूप से ग्वालियर-चंबल से आते हैं। ग्वालियर चंबल से कई कद्दावर नेता हैं जिन्हें पार्टी और सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं, सीएम मोहन यादव मालवा क्षेत्र से आते हैं। विंध्य से डेप्युटी सीएम हैं। क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर निमाड या फिर महाकौशल को साधने के लिए बीजेपी यहां के किसी नेता पर दांव लगा सकती है।

हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपने जा रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कई बड़े नेता अपनी

जगह बनाने में जुटे हैं। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी

शामिल हैं। इधर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो संघ का करीबी होगा, संगठन का कार्यभार उसे सौंपा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन हो



सकता है मध्यप्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष ?

क्या है एमपी कैबिनेट का जातिगत समीकरण ?

डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में सभी वर्गों को साधा गया है। 31 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में सभी जातियों को खुश हो करने की कोशिश की गई थी। पिछड़ा वर्ग के 12 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। पांच एससी और चार एसटी विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि राकेश शुक्ला को भी कैबिनेट में शामिल कर ब्राह्मण समाज को खुश करने की कोशिश की गई थी। सामान्य वर्ग के आठ विधायकों को मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। वहीं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व भी कैबिनेट में है। सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल में पांच महिलाओं को भी जगह मिली है।

कई नामों पर हो रही चर्चा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश के सक्रिय नेता अपने चहेतों का नाम आगे बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैबिनेट मंत्री



भूपेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप, सागर और खुरई में उनकी गुंडई ने प्रदेश भाजपा को पहले भी उनके चयन के लिए कठघरे में खड़ा कर दिया था।

प्रहलाद सिंह पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने करीबी नेताओं का नाम लेकर दिल्ली तक पहुंचे। सूत्रों के अनुसार उज्जैन आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन और मालवा के नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेंद्र

सिंह को बतौर प्रदेश अध्यक्ष नाम आगे बढ़ाया है। जबकि देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर सहित गोपाल भार्गव का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। अभी तक सामने आए सभी नामों पर बारीकी से नजर डाले तो देखने में आता है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को छोड़ सभी नेता प्रदेश अध्यक्ष की काबिलियत रखते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह अपने उपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, सागर और खुरई में उनकी गुंडई ने प्रदेश भाजपा को पहले भी उनके चयन के लिए कठघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे में अब भाजपा दोबारा उनके नाम पर विचार करेगी यह तो संभव नहीं। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के बारे में उन्होंने कहा था कि 'पार्टी स्वीकार करे या ना करे मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा', इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सिंधिया और उनके करीबी भूपेंद्र सिंह के अध्यक्ष बन जाने के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यही नहीं अगर भाजपा की अपनी प्रतिकृति अनुसार कार्यशैली को आगे बढ़ाना है तो भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से बाहर निकलना होगा।

मध्यप्रदेश में अच्छी नहीं है अमृत सरोवर की स्थिति



जगत विजन डेस्क

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहली वाटरबॉडी सेंसस के मुताबिक मध्यप्रदेश में 82,643 कुल जल निकाय हैं। उसमें से 37257 उपयोग में हैं। शेष 45,386 उपयोग में नहीं हैं। आजादी का अमृत महोत्सव काल में अमृत सरोवर (तालाब) योजना शुरू किया गया था। जिसमें देश के 28 राज्य और 5 केन्द्र शासित प्रदेश शामिल थे। सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर को विकसित करना या पुनर्जीवित करना था। जिससे 50 हजार सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य था। इस मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा लिया जाना तय किया गया। मिशन अमृत सरोवर को मनरेगा, 15वें वित्त

**मध्यप्रदेश में 82,643
कुल जल निकाय हैं।
उसमें से 37257 उपयोग
में है। शेष 45,386
उपयोग में नहीं हैं।**

आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना जैसे वाटर शेड, हर खेत को पानी, राज्यों की अपनी योजनाओं के अलावा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के साथ राज्यों और जिलों के माध्यम से काम हुआ है। इस काम के लिए क्राउड फंडिंग और कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

(सीएसआर) जैसी सार्वजनिक योगदान की भी अनुमति दी गई थी। मिशन अमृत सरोवर का ध्यान जल संरक्षण, जन भागीदारी और बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित करने के लिए जल निकायों पर केन्द्रित था। देश भर में 68410 सरोवर निर्माण तथा पुनरूद्धार पर 10419.38 करोड़ रुपये खर्च किये गए। मध्यप्रदेश में 5970 सरोवर निर्माण तथा पुनरूद्धार शुरू किया गया और 5299 पूर्ण हुआ है, जिसमें 737.13 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहली वाटरबॉडी सेंसस के मुताबिक मध्यप्रदेश में 82,643 कुल जल निकाय हैं। उसमें से 37257 उपयोग में है शेष 45386 उपयोग में नहीं है। देशभर के जल निकायों की



स्थिति अच्छी नहीं है। शहरी भारत में हर चार जल निकायों में से लगभग एक उपयोग में नहीं है जबकि ग्रामीण भारत में सात जल निकायों में करीब एक उपयोग नहीं है। अर्थात देश के 24,24,540 कुल जल निकायों में से 3,94,500 उपयोग में नहीं है। भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर दिसम्बर 2023 के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में 22 राज्य और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के अमृत सरोवर सफलता की एक से दो कहानी प्रकाशित किया गया है। परन्तु देश भरके अमृत सरोवर की सफलता में मध्य प्रदेश को स्थान नहीं मिलना कुछ और कहानी बयां कर रहा है। जबकि जबलपुर जिले में 99, कटनी में 115, नरसिंहपुर में 60, छिंदवाड़ा में 295, ग्वालियर में 101, इंदौर में 106, सिंगरौली में 128, सीधी में 157, सिवनी में 88, रीवा में 106, भोपाल में 76, बालाघाट में 100 और मंडला में 105 अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। विभिन्न मिडिया

रिपोर्ट से पता चलता है कि डेढ़ साल चले अमृत सरोवर के दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। विदिशा जिले की सिरोंज जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरेखों में करीब 39 लाख रुपये की लागत से बनाया गया दो अमृत सरोवर तालाब एक बारिश भी नहीं झेल पाया और धाराशायी हो गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला जिला में जनपद पंचायत मोहगांव के ग्राम पंचायत मलवाथर में बने अमृत सरोवर तालाब पहली बारिश में ही पोल खोल कर रख दिया। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और ठकेदार अपनी कमी छुपाने तरह-तरह के बहाने दे रहे हैं। तालाब का जो काम बारिश के पहले ही पूर्ण होना था, उसे अपूर्ण बता कर भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश करते दिखाई दिए। दूसरा इसी जिले में कान्हा नेशनल पार्क के पास बोडा छपरी सरोवर लगभग सूखा पड़ा है। ग्रामिणों का आरोप है कि सरोवर बनाने में गड़बड़ी की गई है। सरोवर का गहरीकरण नहीं किया गया है।

सौंदर्यीकरण को लेकर पेड़ पौधे लगाए गए थे, वे सूख गये हैं। वहीं महिला समूहों द्वारा मिलकर 50 हजार मछलियों के बच्चे छोड़े गए परन्तु पानी नहीं होने से मछलियाँ मर गई। जिससे महिला समूहों को हजारों का नुकसान हो गया। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में 101 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरही ग्राम पंचायत में 57 लाख की लागत से बनाये गए तालाब में बारिश के मौसम में पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन घटिया निर्माण के कारण के चलते पानी का तेजी से रिसाव हो गया और बारिश का मौसम जाने से पहले ही सरोवर सूख गया। ग्रामीणों द्वारा अमृत सरोवर योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही या जांच नहीं हुआ। उपरोक्त कुछ उदाहरणों से अमृत सरोवर योजना में मध्य प्रदेश का स्थान नहीं होने को समझा जा सकता है।

विष्णु देव साय सरकार का एक साल मुख्यमंत्री साय ने तय कर दी है दशा और दिशा

भूपेश सरकार के कुशासन को भूल पट्टी पर लौट रहा प्रदेश

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 13 दिसम्बर को अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा लिया है। इस एक वर्ष में साय सरकार ने जनहित और जनकल्याण के ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले किये हैं जिसने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य हुआ

है। वहीं भूपेश सरकार के कुशासन को भूल वर्तमान सरकार प्रदेश को पट्टी पर लाने का प्रयास कर रही है। भूपेश सरकार में जो कारनाम हुए उनसे सबक लेते हुए बीजेपी सरकार फूंक-फूंक कर कदम बड़ा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 03 दिसम्बर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा

चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश के सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री विष्णुभदेव साय के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई। इस माह ही इस सरकार को अपने कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। साय सरकार अपने एक साल के कार्यकाल

की उपलब्धियों और कार्यों को गिना रही है। छत्तीसगढ़ की लगभग 03 करोड़ आबादी में एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से

विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारकों को दो कारकों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है एक तो यहां की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरी यहां की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। राज्य की नीतियां तय करते समय इन दोनों की अनदेखी नहीं की जा सकती, दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ता है। केन्द्रीय

गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश में माओवादी आतंक के खात्मे के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। केन्द्र के इस फैसले ने राज्य को समृद्धि के रास्ते में आगे जाने के संकल्प को और मजबूती दी है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। लगभग तीन करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत के



नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने पिछले 12 माह में इन सभी मुद्दों पर काम किया है। मुद्दा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य शासन की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना जनकल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किमी के दायरे में आने वाले 96 गांवों का चयन कर शासन के 17

साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले दो प्रमुख कारकों आदिवासी समुदाय और किसान दोनों पर शुरू से ही ध्यान दिया है।

निर्माण में योगदान दे रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले दो प्रमुख कारकों आदिवासी समुदाय और किसान दोनों पर शुरू से ही ध्यान दिया है। राज्य में लोगों को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के वायदे को लेकर आयी साय सरकार आई.टी. और ए.आई आधारित प्रणाली को पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाना शुरू कर दिया है। राज्य में कृषक उन्नति योजना खेती-किसानी के लिए एक नया संबल बनी है। इसके चलते कृषि

समृद्ध और किसान खुशहाल हुए हैं। राज्य में खेती-किसानी को नई उर्जा मिली है। राज्य में उन्नत खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के किसान हितैषी फसलों का असर अब खेती-किसानी में साफ दिखाई देने लगा है। उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग खेती-किसानी में बढ़ा है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिसके एवज में 32 हजार करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप राज्य के किसानों को दो साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान की मूल्य की अंतर राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस तरह किसानों को कुल मिलाकर 49 हजार करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए। छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

की सरकार ने समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ कर दी है। इस साल राज्य में बेहतर बारिश एवं अनुकूल मौसम के चलते धान के विपुल उत्पादन की उम्मीद है। इसको देखते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन अनुमानित है। राज्य में किसानों से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की जाएगी। राज्य के किसानों को खेती-किसानी के लिए वर्तमान खरीफ सीजन में 6500 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिए जा चुके हैं। अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां के किसान अब ई-नाम पोर्टल (कृषि बाजार) के माध्यम से अपने उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा

अनुज्ञापिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के किसानों से उनकी उपज खरीद सकेंगे, इससे उत्पादक किसानों को लाभ होगा। किसानों को उन्हें पंजीयन की जरूरत नहीं होगी।

नक्सलवाद पर कसी नकेल

राज्य के बस्तर और अन्य हिस्सों में माओवादी आतंक को समाप्त करने के लिए सख्ती से कदम उठाए गए हैं। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार आपसी तालमेल बनाए हुए हैं। माओवादी आतंक भी अब कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। यहां नियद नेल्लानार जैसी नवाचारी योजना से लोगों का सरकार के प्रति फिर से विश्वास लौट रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्प के आस-पास के दायरे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकार के शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में युवाओं को तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण





की सुविधा दी जा रही हैं। इस पहल से आदिवासी समुदाय की युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार की योजना है कि 2025 तक प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है।

13 दिसंबर 2023 को सीएम बने थे विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 03 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। तब राज्य में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। हार के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विष्णुदेव साय के साथ विजय शर्मा और अरूण साव ने डेप्युटी सीएम पद की शपथ ली थी।

मोदी की गारंटी के पांच वादे, जिन्हें 01 साल में साय सरकार ने किया पूरा धान का समर्थन मूल्य

विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में 3100 रुपये के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। राज्य में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब धान की खरीदी चालू थी। उस बार सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी थी। इस बार भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी हो रही है। एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।

18 लाख लोगों के लिए आवास योजना

छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब आवास योजना को लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया था। बीजेपी

ने चुनाव के दौरान 18 लाख लोगों को आवास देने की घोषणा की थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही मोदी की गारंटी के पहले वादे 18 लाख लोगों के आवास को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद राज्य में आवास योजना पर तेजी से काम हो रहा है।

महतारी वंदन योजना

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की विवाहित महिलाओं को 1 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना के फार्म विधानसभा चुनाव के दौरान ही भरे जाने लगे थे। इस योजना को राज्य की गेम चेंजर योजना माना गया। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मार्च में इस योजना को लागू किया गया। राज्य की 70 साल महिलाओं को



महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया था। महिलाओं की उन्नति के लिए सरकारी कई कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस की सरकार ने महिला समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें दोबारा यह काम सौंप दिया है।

रामलला दर्शन योजना की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने खर्च पर पात्र श्रद्धालुओं को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भेजती है। बता दें कि भगवान राम को

छत्तीसगढ़ में भांजा राम कहा जाता है।

पीएससी घोटाले की भी सीबीआई जांच

भूपेश बघेल की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग में घोटाले का मामला सामने आया था। मोदी की गारंटी में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही गई थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। सीबीआई ने लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टोमन सिंह सोमवानी को गिरफ्तार किया है।

सुशासन से बदली प्रदेश की तस्वीर

युवा छत्तीसगढ़ पिछले 12 महीने के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। सड़कों, रेल लाइनों समेत अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य

ने बीते 24 वर्षों में निरंतर प्रगति की है। रायपुर एयरपोर्ट देश के तमाम बड़े शहरों से जुड़ गया है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में शुमार होने लगा है। गांव-गांव तक बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राजधानी रायपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। बस्तर में एनएमडीसी का स्टील प्लांट प्रारंभ हो चुका है। राज्य की कला, संस्कृति, वनोपज, हस्तशिल्प आदि की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। आज से 24 साल पहले जब राज्य बना था, तब से लेकर साल भर पहले तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या



थी। विष्णु देव साय की सरकार की कुशल रणनीति और प्रभावी कार्रवाई के चलते अब राज्य में नक्सल समस्या समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही विष्णु सरकार ने जनहित में फैसले लेने और उसे अमल में लाने को लेकर एक्शन में आ गई थी। सरकार गठन के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18,12,743 जरू रतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। राज्य के 13 लाख किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस के अवसर 25 दिसंबर 2023 को 3176 करोड़ रुपये जारी किया। मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्वंटल के मान से 3100 रुपये के दाम पर धान की खरीदी की। 25 लाख 75 हजार किसानों

को धान का समर्थन मूल्य 32 हजार करोड़ रुपये तत्काल जारी किया और 12 जनवरी 2024 को 13,320 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान भी कर दिया। खरीफवर्ष 2023-24 में किसानों से रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी विष्णु देव साय की सरकार ने की। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिल रहा है। संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने की योजना भी लागू होने जा रही है। विष्णु सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अंत्योदय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। प्रशासन में पारदर्शिता, आम जनता की सुनवाई, नारी, गरीब, किसान, युवा के लिए अवसरों के द्वार खोलने का काम इस सरकार ने किया है।

औद्योगिक विकास की पहल

राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति

2024-2030 एक नवम्बर से लागू हो गई है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा एवं विस्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति में कई रियायती प्रावधान किए गए हैं। उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। इस पोर्टल पर एक बार आवेदन करने पर सभी विभागों से क्लीयरेंस मिलेगा। नया रायपुर को आईटी का हब बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। दो आईटी कंपनियों से एमओयू किया गया है तथा उन्हें फर्निशुड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य में लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन प्रस्तावित है। कोरबा, बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का निर्माण किया जा रहा है।

भोपाल गैस त्रासदी

जहरीले कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती



योगेश कुमार गोयल

भोपाल शहर में वर्ष 1984 में हुई भयानक गैस त्रासदी, पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और हृदयविदारक औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। 2-3 दिसम्बर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली

गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। दुर्घटना के चंद घंटे के भीतर कई हजार लोग मारे गए। मौतों का सिलसिला उस रात से शुरू होकर लंबे अरसे तक अनवरत चलता रहा। इस हादसे के 40 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यह इस कदर विचलित कर देने वाला हादसा था कि इसमें मारे गए लोगों को

सामूहिक रूप से दफनाया या अंतिम संस्कार किया गया। करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के सभी तरह के पेड़ बंजर हो गए थे।

एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का



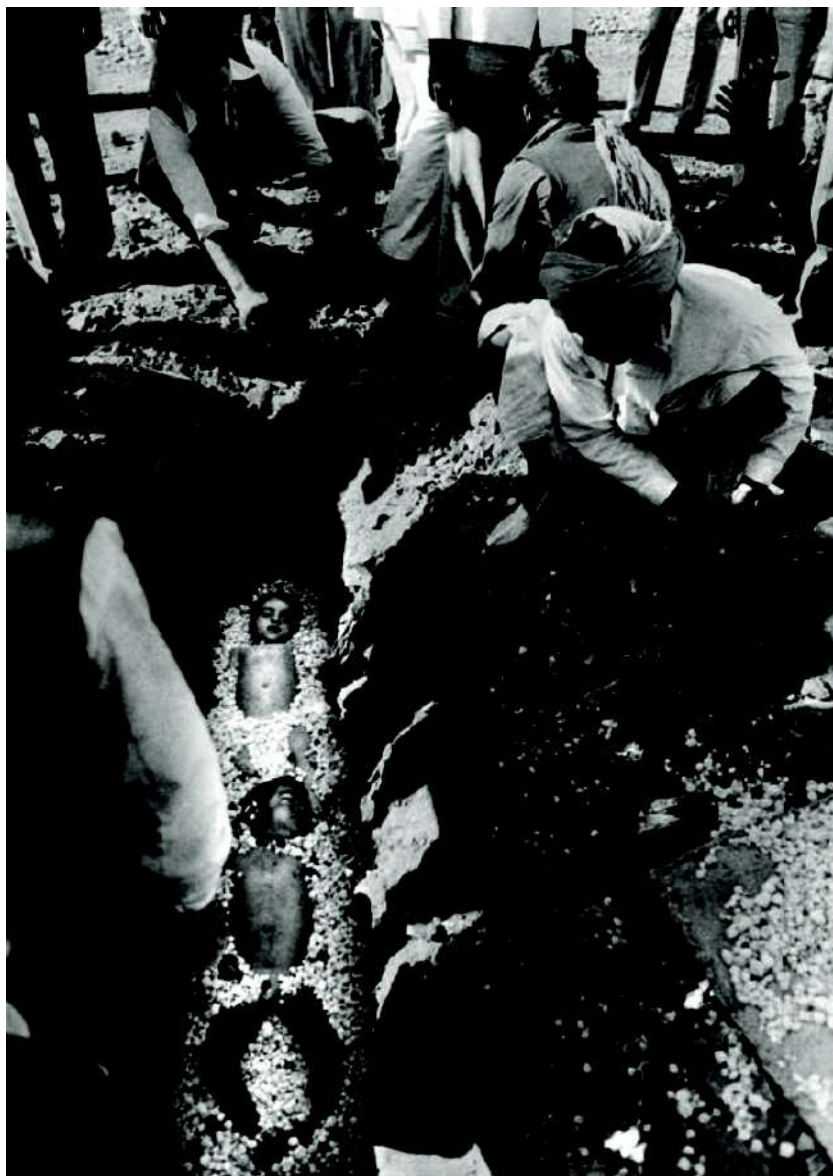
कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी तिल-तिलकर मरने को विवश हुए। इनमें से बहुत से लोग कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और सालों बाद भी इसके दुष्प्रभाव खत्म नहीं हो रहे।

गैस त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बाद भी इस त्रासदी से पीड़ित होने वालों के जख्म हरे हैं। विषैली गैस के सम्पर्क में आने वाले लोगों के परिवारों में इतने वर्षों बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के

मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुईं और गैस से करीब 558125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा

है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर





मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया और जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई। अचानक हुए जहरीली गैस के रिसाव से बने गैस के बादल हवा के झोंके के साथ वातावरण में फैल गए और इसकी चपेट में आनेवाले लोग मौत की नींद सोते गए।

इस दुर्घटना के चार दिनों बाद 7

**गैस त्रासदी के 40 साल
बीत जाने के बाद भी इस
त्रासदी से पीड़ित होने वालों
के जख्म हरे हैं। विषैली गैस
के सम्पर्क में आने वाले
लोगों के परिवारों में इतने
वर्षों बाद भी शारीरिक और
मानसिक रूप से अक्षम
बच्चे जन्म ले रहे हैं**

दिसम्बर 1984 को यूसीआईएल अड्यक्ष एवं सीईओ वारेन एंडर्सन की गिरफ्तारी हुई थी किन्तु विड बना देखिये कि इतने भयानक हादसे के मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के महज छह घंटे बाद मात्र 2100 डॉलर के मामूली जुर्माने पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद वह अवसर का लाभ उठाते हुए भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका भाग गया, जिसे भारत लाकर सजा देने की मांग निरन्तर उठती रही लेकिन भारत सरकार अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हुई। अंततः 29 सितम्बर 2014 को वारेन एंडर्सन की मौत हो गई। इस हादसे पर वर्ष 2014 में भोपाल एम्प्रेयर फॉर रेन नामक फिल्म भी बन चुकी है।

अंधेपन के भी शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक करीब 8 हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर हो गई थी जबकि करीब 8 हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों के चलते मारे गए थे।

बताया जाता है कि कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर

20 डिग्री था। पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल बचाने के लिए मिंक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 03 दिसम्बर 1984 को इस कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी



भले ही गैस रिसाव के करीब आठ घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था किन्तु हकीकत यह है कि इस गैस त्रासदी के 40 वर्षों बाद भी भोपाल उससे उबर नहीं पाया है। हादसे से पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई सरकारें आज तक नहीं कर पाई हैं। सरकारों का इस पूरे मामले में रुख संवेदनहीन ही रहा है। कई रिपोर्टों में इस क्षेत्र में भूजल प्रदूषण की पुष्टि होने के बाद भी सरकार द्वारा जमीन में दफन जहरीले कचरे के निष्पादन की कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है।

दरअसल इस भयावह गैस त्रासदी के बाद हजारों टन खतरनाक अपशिष्ट भूमिगत दफनाया गया था और सरकारों ने भी स्वीकार किया है कि यह क्षेत्र दूषित है। विभिन्न रिपोर्टों में बताया जाता रहा कि यूनियन कार्बाइड संयंत्र के आसपास की 32 बस्तियों का भूजल प्रदूषित है और यह सरकारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा रही कि गैस पीड़ित वर्ष 2014 तक इसी प्रदूषित

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड कारखाने के 10 टन कचरे का निस्तारण इन्दौर के पास पीथमपुर में किया जा चुका है लेकिन पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ा, यह एक रहस्यमयी पहली है। यहां जहरीली गैसों का खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि उस त्रासदी के 346 टन जहरीले कचरे का निस्तारण अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो हादसे की वजह बने यूनियन कार्बाइड कारखाने में कवर्ड शेड में मौजूद है। इसके खतरे को देखते हुए यहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है।

भूजल को पीते रहे। हालांकि वर्ष 2014 में इन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन डाली गई लेकिन तब तक जहरीले रसायन लोगों के शरीर में गहराई तक घुल चुके थे। स्थिति यह है कि पानी की कमी होने पर लोग आज भी इस दूषित जल का उपयोग कर लेते हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड कारखाने के 10 टन कचरे का निस्तारण इन्दौर के पास पीथमपुर में किया जा चुका है लेकिन पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ा, यह एक रहस्यमयी पहली है। यहां जहरीली गैसों का खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि उस त्रासदी के 346 टन जहरीले कचरे का निस्तारण अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो हादसे की वजह बने यूनियन कार्बाइड कारखाने में कवर्ड शेड में मौजूद है। इसके खतरे को देखते हुए यहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। जहरीली गैस के कारखाने से निकले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए सरकार कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पाई और करीब 40 सालों से पड़ा यह कचरा कारखाने के आसपास की जमीन, जल और वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस जहरीले कचरे का निस्तारण बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि भारत के पास इसके निस्तारण की तकनीक और विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं।

अब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर छिड़ गया है नया विवाद दावा दरगाह के नीचे है शिव मंदिर



विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा उबाल पर है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर 2024 को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी है। विष्णु गुप्ता ने अजमेर: हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का भी हवाला दिया गया है। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। इसको लेकर 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका मंजूर कर दी।

समता पाठक

अजमेर दरगाह को लेकर राजनीति चरम पर है। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर निचली अदालत में एक याचिका भी डाली गई, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया। जिसके बाद से राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि मथुरा, वाराणसी और धार में

विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर 2024 को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी है।

ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। विष्णु गुप्ता की ओर से कोर्ट में पेश याचिका में उन्होंने 168 पेज की अजमेर: हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के पेज नं. 93, 94, 96 और 97 का हवाला दिया। उन्होंने कहा

अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब अजमेर दरगाह पर छिड़ गई बहस

मस्जिदों और दरगाहों पर इसी तरह के दावे किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा उबाल पर है। इस

विष्णु गुप्ता ने अजमेर: हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का भी हवाला दिया गया है। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। इसको लेकर 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका मंजूर कर दी। इधर, सिविल जज मनमोहन चंदेल

कि जब मैंने हरबिलास शारदा की किताब को पढ़ा, तो उसमें साफ-साफ लिखा था कि यहां पहले ब्राह्मण दंपती रहते थे। यह दंपती सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे।

- याचिका में पहला तर्क है कि दरगाह



में मौजूद बुलंद दरवाजा की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है, इनकी नक्काशी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है, कि दरगाह से पहले यहां हिंदू मंदिर रहा होगा।

- दरगाह के उपरी हिस्से को देखे, तो

वहां हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। इनके गुंबदों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण करवाया गया।

- विष्णु गुप्ता का तीसरा तर्क, देश में

जहां भी शिव मंदिर हैं, वहां पानी और झरने जरूर होते हैं, ऐसा ही अजमेर दरगाह में भी है।

पूजा स्थल अधिनियम पर बवाल

दरअसल, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत अयोध्या को

मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों?: औवैसी



अजमेर दरगाह केस मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यहीं है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं, लेकिन बीजेपी-आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं, फिर निचली अदालतें प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहां जाएगा? यह देश के हित में नहीं है। पीएम मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। यह सब बीजेपी-आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है।

इनका कहना है...

सस्ती लोकप्रियता के कारण समाज में ऐसी हरकत: सै. नसरुद्दीन चिश्ती



अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सन 1950 में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज एक्ट की कवायद चल रही है, उस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज गुलाम हसन की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा हुई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दरगाह का पूरा इतिहास भी था। रिपोर्ट में कौन सी इमारत दरगाह में कब तामीर की गई और किसने बनाई है इसका उल्लेख है, लेकिन रिपोर्ट में दरगाह में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर होने का उल्लेख नहीं है। 800 साल में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। देश में कब तक हम मंदिर-मस्जिद विवाद में उलझे रहेंगे। यह परिपाटी बिल्कुल गलत है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इसको लेकर कानून बनाया जाए। सन 1947 के पहले के विवाद अलग कर दिया जाए। चिश्ती ने कहा कि आए दिन मस्जिद और दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इससे एक दूसरे के प्रति कटुता और अविश्वास की भावना बढ़ती है, जो समाज के लिए गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में वकीलों से कानूनी राय लेकर पक्ष रखना होगा, तो वह जरूर रखेंगे।



सर्वे से क्या समस्या: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अजमेर में न्यायालय ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। अगर न्यायालय ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है तो इसमें क्या समस्या है? यह सच है कि जब मुगल भारत आए, तो उन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अब तक केवल तुष्टिकरण किया है। अगर (जवाहरलाल) नेहरू ने 1947 में ही इसे रोक दिया होता, तो आज न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

छोड़कर, देश भर में धार्मिक संरचनाओं पर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बनाए रखने का कानून बना है। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई

चंद्रचूड़ ने तर्क दिया था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है।

अजमेर दरगाह का इतिहास: एक नजर में

बता दें कि ईरान (फारस) के एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया था और मुगल सम्राट हुमायूँ ने उनके सम्मान में एक दरगाह बनवाई थी। उनके पोते, सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थयात्रा करते थे।

इनका कहना है...



इससे विवाद बढ़ेगा: महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले से विवाद बढ़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा भी ऐसे फैसले का सीधा परिणाम थी। मुफ्ती ने आगे कहा कि देश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बदौलत एक भानुमती का पिटारा खुल गया है, जिससे अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों के बारे में विवादास्पद बहस छिड़ गई है।



कपिल सिब्बल ने जताई नाराजगी

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट से कोर्ट के फैसले से खासी नाराजगी जताई। सिब्बल ने कहा, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर... हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? और क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए!

भाजपा ने कोर्ट का किया समर्थन

कोर्ट के इस फैसले की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है। विपक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह पर चादर भेजी थी, तो अब क्या हुआ। उधर, भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि इस तरह के विवादित ढांचे के नीचे मंदिरों की मौजूदगी की जांच करने का निर्णय उचित है।

अकबर और उनके पोते शाहजहां ने अजमेर दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई थीं।

अजमेर शरीफ दरगाह की गिनती भारत की सबसे बड़ी पवित्र धार्मिक स्थलों में की जाती है।

20 दिसम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में क्या ?

अजमेर दरगाह विवाद मामले में 27 नवम्बर को याचिका मंजूर कर ली गई। इसको लेकर 20 दिसम्बर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर, अगली सुनवाई को लेकर सियासत हो या आम, हर जगह हलचल मच गई है कि आखिर अब क्या होगा? वहीं अगली सुनवाई पर कोर्ट के

आदेश पर अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इधर, सियासत में भी बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढा समेत कई नेताओं ने भी इस याचिका विरोध

भारत में वक्फ का इतिहास और कानूनी विवाद

वक्फ बोर्ड की यह बहस हमें 12वीं सदी में ले जाती है, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में वक्फकी नींव रखी थी। आज वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है, जिस पर केंद्र सरकार नया कानून लाकर नियंत्रण करना चाहती है। तमिलनाडु के एक किसान की जमीन वक्फ बोर्ड की क्या निकली कि देश में फिर से वक्फ कानून पर तगड़ी बहस छिड़ गई। यह वाकया कोई अकेला मामला नहीं था, आसपास के 18 और गांवों को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया। भारत में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, जो लगभग 3,804 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ दो गांवों के दान से हुई थी। कई जानकार मानते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद, वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार हैं। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में यह फैली।

वक्फका मतलब समझिए

वक्फ इस्लामी दान के सिद्धांतों पर आधारित है। वक्फ का मतलब है एक स्थायी दान, जहां संपत्ति को धार्मिक, परोपकारी, या सामुदायिक कार्यों के लिए अलग रखा जाता है, जिसका स्वामित्व अल्लाह को सौंप दिया जाता है। इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी, एक बार संपत्ति अल्लाह को सौंप दी गई, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस

संसद के चालू शीतकालीन सत्र में BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक



भारत में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, जो लगभग 3,804 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ दो गांवों के दान से हुई थी। कई जानकार मानते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद, वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार हैं। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में यह फैली।

पर हंगामा और गरमा गरम बहस हुई। यह विधेयक, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार करना है, फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार-विमर्श के लिए है। सूत्रों के मुताबिक, अब वक्फ विधेयक फरवरी 2025 में बजट सत्र के दौरान पेश किया जा

सकता है।

क्या है वक्फ का इतिहास ?

वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चाओं और बहसों के बीच, यह जानना दिलचस्प है कि अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत में वक्फ की अवधारणा कैसे आई। मोहम्मद गौरी ने



1175 में मुल्तान के इस्माइली शासक को हराया था। उसके बाद 1192 में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के साथ ही दिल्ली और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा उसके शासन में आ गया। गौरी ने पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के बाद 1185 में पहला दर्ज वक्फ दान किया था। इतना ही नहीं, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की जीत से भारत में इस्लामी शासन की शुरूआत हुई। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद, उसके गुलामों ने उसके राज्य की बागडोर संभाली और गुलाम वंश की स्थापना की। उन मुस्लिम शासकों और बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले सुल्तानों ने इस प्रणाली को संस्थागत रूप दिया।

क्या था उद्देश्य?— अयनुल मुल्क मुल्तानी की फरसी किताब इन्शा-ए-महर के अनुसार, सुल्तान मुइजुद्दीन सैम, जिन्हें मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, ने मुल्तान की जामा मस्जिद को दो गांव

उपहार में दिए और उनके प्रबंधन का काम शेख-अल-इस्लाम को सौंपा, जो एक प्रमुख धार्मिक नेता को दी जाने वाली उपाधि थी। मुल्तानी की किताब उस दौर के आधिकारिक पत्राचार में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों पत्रों और उनके नमूनों का संग्रह है।

1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की जीत से भारत में इस्लामी शासन की शुरूआत हुई। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद, उसके गुलामों ने उसके राज्य की बागडोर संभाली और गुलाम वंश की स्थापना की।

इतिहासकार विपुल सिंह की किताब इंटरप्रेटिंग मेडिवल इंडिया के अनुसार, पत्र संख्या 16 में कहा गया है कि शुरूआती वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। वे मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और अन्य सामुदायिक कल्याण संस्थानों का समर्थन करते थे।

धीरे-धीरे बढ़ती चली गई संपत्ति

दिल्ली सल्तनत के तहत वक्फ की अवधारणा बढ़ी और जमीन वक्फ संपत्ति में तब्दील होती गई। विद्वान अमीर अफाक अहमद फैत्री के अनुसार, बदायूं में मिरान मुलहिम की कब्र, बिलग्राम में ख्वाजा मजद अल-दीन का मकबरा, गोपामान के अजमत टोला में लाल पीर की दरगाह, बदायूं में बिल्सी रोड पर कब्रिस्तान और उत्राव के असिवान में गंज-ए-शहीदान, भारत में कुछ शुरूआती वक्फ संपत्तियों के उदाहरण हैं। सितंबर में जारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एक व्याख्याता

के अनुसार, 'जैसे-जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले-फूले, वैसे-वैसे भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई।'

वक्फसंपत्तियों का रखरखाव किनके पास था ?

दिल्ली सल्तनत के दौरान, इस प्रथा को गति मिली क्योंकि इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे बाद के सुल्तानों ने न केवल मौजूदा वक्फ को संरक्षित किया, बल्कि नए भी स्थापित किए। वक्फ का प्रबंधन महत्वपूर्ण था और दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक और वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि दीवान-ए-विजारत, या प्रधानमंत्रियों को उनकी देखरेख का काम सौंपा गया था। इतिहासकार विपुल सिंह लिखते हैं कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले लोगों के महत्व को दर्शाते हुए, उनकी सुल्तान तक सीधी पहुंच थी। कैपेसिटी बिल्डिंग

कमीशन, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायिक और धार्मिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार दीवान-ए-रसालत के कार्यालय को भी वक्फ संपत्तियों के रखरखाव का काम सौंपा गया था।

वक्फ की इनकम का सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल

वक्फ से प्राप्त आय से हौज (जलाशय), मदरसों, सड़कों और सराय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और रख रखाव में मदद मिलती थी। प्रमुख उदाहरणों में बदायूं में शम्सी मस्जिद शामिल है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान किया गया था, और लाहौर में सुल्तान कुतुबुद्दीन के मकबरे के रखरखाव के लिए वक्फ शामिल है। 14वीं सदी के विद्वान जियाउद्दीन बरनी ने तारीख-ए-फिरोज शाही में लिखा है, 'यह राजाओं में एक रिवाज है, जब वे सिंहासन पर होते हैं, तो धार्मिक लोगों को गांव और जमीनें देने के लिए ताकि उनके मकबरों के रखरखाव

और मरम्मत के लिए साधन उपलब्ध कराए जा सकें।'

वक्फके प्रबंधन को लेकर खींचतान

हालांकि मध्ययुगीन काल में वक्फ का प्रशासन विकेन्द्रीकृत था, लेकिन यह अत्यधिक संगठित था। स्थानीय न्यासी, जिन्हें मुतवल्ली के नाम से जाना जाता है, दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करते थे, जबकि सदर-उस-सुदूर और काजी जैसे अधिकारी इस्लामी कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करते थे। विद्वान अमीर अफाक अहमद फैजी के अनुसार, शासक, वक्फ की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, कभी-कभी कुप्रबंधित संपत्तियों को बहाल करने या भ्रष्ट न्यासियों को बदलने के लिए हस्तक्षेप करते थे। उदाहरण के लिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नए न्यासियों की ओर से वक्फ की उपेक्षा करने के बाद मूल न्यासियों को फिर से नियुक्त किया, और उनके संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए सुधार शुरू किए। खिलजी ने 13वीं





सदी में शासन किया था।

बाबर का शासन और वक्फ

पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के लोधी शासकों के पतन के बाद, सत्ता की बागडोर बाबर के हाथों में आ गई, जो उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी से आया था और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों के अधीन, वक्फ संस्था और अधिक फली-फूली, अकबर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने महत्वपूर्ण संपत्तियों को बंदोबस्ती दी। लखनऊ में अकबर का फरांगी महल और शाहजहां का ताजमहल इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। मध्ययुगीन काल के दौरान वक्फ के पैमाने और महत्व का खुलासा करते हुए, विद्वान अमीर अफाक अहमद फैज़ी लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां की ओर से ताजमहल का निर्माण लगभग 30 गांवों और एक परगना (प्रांत) की ओर से सहायता प्रदान की गई थी, जिन्हें बंदोबस्ती दी गई थी।

जगत विजन

कैसे हुआ वक्फ की संपत्ति का विस्तार?

समय के साथ, जैसे-जैसे मुस्लिम समुदाय ग्रामीण इलाकों में बसते गए, वक्फ की अवधारणा ग्रामीण भारत में विस्तारित होती गई। यह विस्तार कई वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के इस्लाम में धर्म परिवर्तन के साथ भी हुआ। विभिन्न मुस्लिम राजवंशों, बड़े और छोटे, के अधीन विकसित होने के बाद, वक्फ प्रणाली ने 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम की शुरूआत के साथ ब्रिटिश शासन के दौरान एक और औपचारिक संरचना प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद, इसे 1954 के वक्फ अधिनियम द्वारा बदल दिया गया, जिसे बाद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करने के लिए 1995 और 2013 में अपडेट किया गया, जिससे वे भूमि प्रबंधन में प्रमुख खिलाड़ी बन गए।

वक्फकी देखरेख में लाखों संपत्ति

यह हमें 21वीं सदी में लाता है। वक्फ भारत में सबसे बड़ी भूमिधारक संस्थाओं में से एक बन गया है, जो कई तरह की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। आक्रमणकारी गौरी की ओर से वक्फ को दिए गए दो गांवों से लेकर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन इसके संगठित विस्तार तक, आज, वक्फ बोर्ड लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि को कवर करने वाली 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों की देखरेख करते हैं। वक्फ बोर्डों की ये विशाल शक्तियां और उनसे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां वही हैं जिन्हें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संशोधन विधेयक के साथ दूर करने की मांग कर रही है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पूरी वक्फ अवधारणा 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की ओर से शुरू की गई थी, जिसने दो गांव उपहार में दिए थे।

भोपाल, दिसम्बर-2024



सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय

सेवा सुशासन और जनकल्याण का अडिग संकल्प



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नागरिक सुविधा और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीकी सुधार डिजिटलाइजेशन, ई-टिकॉर्ड के माध्यम से आम-जन के कार्यों को आसान बनाना और हितधारकों को सीधा लाभ देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने सुशासन और नागरिक सेवा को प्राथमिकता देकर हर वर्ग का लाभ सुनिश्चित किया है। इन अभूतपूर्व प्रयासों से मध्यप्रदेश अब उन्नति के नए युग में प्रवेश कर रहा है।



- नामांतरण, बंटवारा जैसे विभिन्न राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए सभी 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य।
- संपदा 2.0 रजिस्ट्री के लिए ई-पंजीयन एवं ई-स्टैम्पिंग की नवीन प्रणाली। दस्तावेजों के ऑनलाइन निष्पादन, डीड वेलिडेशन आदि कार्य होंगे आसान।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन। कानून व्यवस्था के साथ बढ़े पैमाने पर किए गए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण।
- राजस्व महाअभियान के दोनों चरणों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण।
- जिला, संभाग, तहसील आदि की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने का निर्णय।
- मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री अब स्वयं भरेगे अपना इनकम टैक्स।
- प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर 1 जुलाई, 2024 से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट वेकिंग पॉइंट की व्यवस्था शुरू।
- वॉरेंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग प्रारंभ। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।
- प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% माता-पिता को देने का निर्णय।
- 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर डीमड अनुज्ञा प्राप्त करने और 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था लागू।
- बालाघाट के कमकोदावर में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को शूल चटाने वाले 24 शासकीय पुलिस सेवकों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
- प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी।
- शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण।
- भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण।



R.O.No. D19198/24

प्रकृति के सम्मान का उत्सव



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के लिए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
की अभिनव पहल

प्रदेशभर की
गौ-शालाओं में
गोवर्धन पर्व का
सामुदायिक आयोजन



प्रगति और पर्यावरण
के प्रति सजगता की
मिसाल बनता
मध्यप्रदेश

- प्रदेश में संचालित 1,500 से अधिक गौ-शालाओं में 3.30 लाख गौ-वंश का पालन। शीघ्र ही लगभग 2,500 नई गौ-शालाएं प्रारंभ होगी जिनमें 4.50 लाख गौ-वंश का पालन हो सकेगा।
- गौ-वंश के बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये की जा रही है।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12,000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी।
- देश में सर्वाधिक 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करने वाले मध्यप्रदेश में गौ-वंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा।
- दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
- गौ-शालाओं का बजट 150 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ग्यालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना।

R.O.No. D19198/24

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

आकल्पना : मध्यप्रदेश माध्यम/2024



21ST ASEAN-INDIA SUMMIT

10 OCTOBER 2024, VIENTIANE, LAO PDR



एशियाई समाजवाद में है भारत की विदेश नीति की स्थिरता

रघु ठाकुर

यह कहना विचित्र सा लगेगा कि दुनिया एकता की तलाश विभेद में करती है। विशेषतः एशियाई देश जिसमें भारत भी शामिल है, इस अनिश्चितता की समस्या से मुक्त नहीं है। बीसवीं सदी के मध्य में दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया दो सामरिक धड़ों में विभाजित थी एक नाटो (नार्थ एटलान्टिक ट्रीटी) दूसरा नाटो मुख्यतः अमरीकी शक्ति के साथ चलने वाले देशों का संगठन था। दूसरा रूस, चीन व कम्युनिस्ट देशों की ताकत के साथ एक

बीसवीं सदी के मध्य में दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया दो सामरिक धड़ों में विभाजित थी एक नाटो (नार्थ एटलान्टिक ट्रीटी) दूसरा नाटो मुख्यतः अमरीकी शक्ति के साथ चलने वाले देशों का संगठन था। दूसरा रूस, चीन व कम्युनिस्ट देशों की ताकत के साथ एक समझौते का संगठन है।

समझौते का संगठन है। नाटो, रूस, चीन के खतरों के विरुद्ध अपने संगठन के देशों को सुरक्षा मुहैया कराता था। दूसरा अमेरिकी याने नाटो के हमलों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया संगठन था। उस समय दुनिया इन दो ही शक्ति के धड़ों में विभाजित थी। परन्तु कालान्तर में कई शक्ति के केंद्र उभरे हैं और नाटो और दूसरे की भूमिका या तो सिकुड़ी है या बिखरी है। 1950 में आजादी के बाद भारत दोनों धड़ों से अलग था। और उसने भारत, अरब, युगोस्लाविया आदि देशों के साथ गुटनिरपेक्ष देशों का एक

संगठन तैयार करने में सहभागिता की।

1950 और उसके बाद नेहरू, नासिर, टीटो की चर्चा दुनिया में युद्ध व हथियार की शक्ति से हटकर एक निर्गुट संगठन बनाने के रूप में हुई थी। इस गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने भारत और दुनिया को दो शक्तिशाली धड़ों के प्रभाव से बचाकर एक मंच विकसित करने की आशा जगाई थी। हालांकि इस गुट निरपेक्ष संगठन के ये तीन देश सामरिक, आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे और अर्थ व शस्त्र से समर्थ दुनिया का कोई

बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष नीति के दस्तावेज को डॉ. लोहिया ने ही तैयार किया था। जिस पर कांग्रेस व तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल ने मोहर लगाई थी। इक्कीसवीं सदी के आते-आते सामरिक तबके में शक्तियों के केंद्र बदल गए हैं अब दुनिया दो ध्रुवीय नहीं रही बल्कि एक अर्थ में बहु ध्रुवीय बन गई है। चीन भले ही रूस का वैचारिक भाई रहा परन्तु उसने कभी भी अपने मन से रूसी श्रेष्ठता या वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। 1960 के बाद तो,

सब में रूस की भूमिका लगभग एक मूकदर्शक व समर्थक जैसी बनी रही। इन घटनाओं से नाटो और सेंटो का प्रभाव कम हुआ। वियतनाम में सारे हथियारों के प्रयोग के बाद भी अमेरिकी पराजय के बाद अमेरिका और नाटो की भूमिका अविश्वनीय और सीमित हुई।

इक्कीसवीं सदी के आते आते दुनिया ने नाटो और सेंटो से हटकर तथा यू.एन.ओ. से भी इतर अपनी अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार देशों के समूह बनाने शुरू किये।



मजबूत विकल्प या उस ताकतवर दुनिया से पीड़ित देशों के लिए कोई सुरक्षा देने की स्थिति में व्यावहारिक रूप से नहीं थे। ये केवल एक नैतिक समर्थन कर सकते थे। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति यद्यपि केवल नेहरू सरकार की देन नहीं थी बल्कि यह आजादी के आन्दोलन और महात्मा गाँधी की कांग्रेस की देन थी।

डॉ. लोहिया के जर्मनी से पढ़कर लौटने तथा कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग का सचिव

जगत विजन

याने चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के ग्यारह वर्ष बाद चीन ने अपनी वैश्विक व विदेश नीति की भूमिका को रूस से स्वतंत्र रूप से अदा करना शुरू कर दिया था। 1960-70 के बाद चीन-रूस के भी समानंतर खड़े होने लगा। अपने प्रभाव का फैलाव आसपास के देशों में करने लगा था। 1959 में उसने सैन्य शक्ति से तिब्बत पर कब्जा किया। पंचशील समझौते के दो साल बाद ही भारत की उत्तरी सीमा पर हमला कर भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। इन

1991 में स्व. नरसिंह राव की सरकार ने लुक टू द ईस्ट के नाम से एक नई विदेश नीति की शुरुआत की। उन्होंने पाकिस्तान से भिन्नता व सार्क संगठन की भारतीय विदेश नीति के बदलने की शुरुआत की। दरअसल 1980 के बाद सार्क की चर्चा (दक्षिण एशियाई देशों) शुरू हुई थी। इसके मूल में बांग्लादेश के विद्वान थे जिन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के एक आर्थिक संगठन की कल्पना प्रस्तुत की।

यह भी एक संभावना है कि उनकी इस

भोपाल, दिसम्बर-2024

कल्पना के पीछे अमेरिका का कुछ संकेत रहा हो। क्योंकि सार्क में चीन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार शामिल थे। यह नीति एक प्रकार से चीन से भिन्न और पड़ोस के दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चीन के मुकाबले खड़ा करने की नीति थी। इस नीति का भारत की सरकार ने, साम्यवादियों व लगभग सभी सदस्यीय दलों ने समर्थन किया। यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोगों ने दक्षिण देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था। परन्तु 1991 में स्व. नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सार्क से हटकर एक नई नीति की रचना की। लुक टू द ईस्ट की इस नीति के तहत पूर्वी एशिया याने चीन की तरफ फिर दोस्ती के चश्मे से देखना शुरू किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

1. उस समय अमेरिका व चीन के बीच मित्रवत सम्बन्ध शुरू हो गए थे व व्यापारिक संबंध और चीन अमेरिका के आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्ध भी पिघलने लगे थे। अमेरिका ने अपना बाजार चीन के लिए खोला था। तथा चीन ने अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश देना शुरू किया था। यह जुमला चल पड़ा था कि अब विदेश नीति व रिश्ते सरकारें या राजनीति नहीं बरन व्यापार तय करेगा।

2. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लादेन के हमले के बाद अमेरिका का मुख्य लक्ष्य लादेन को

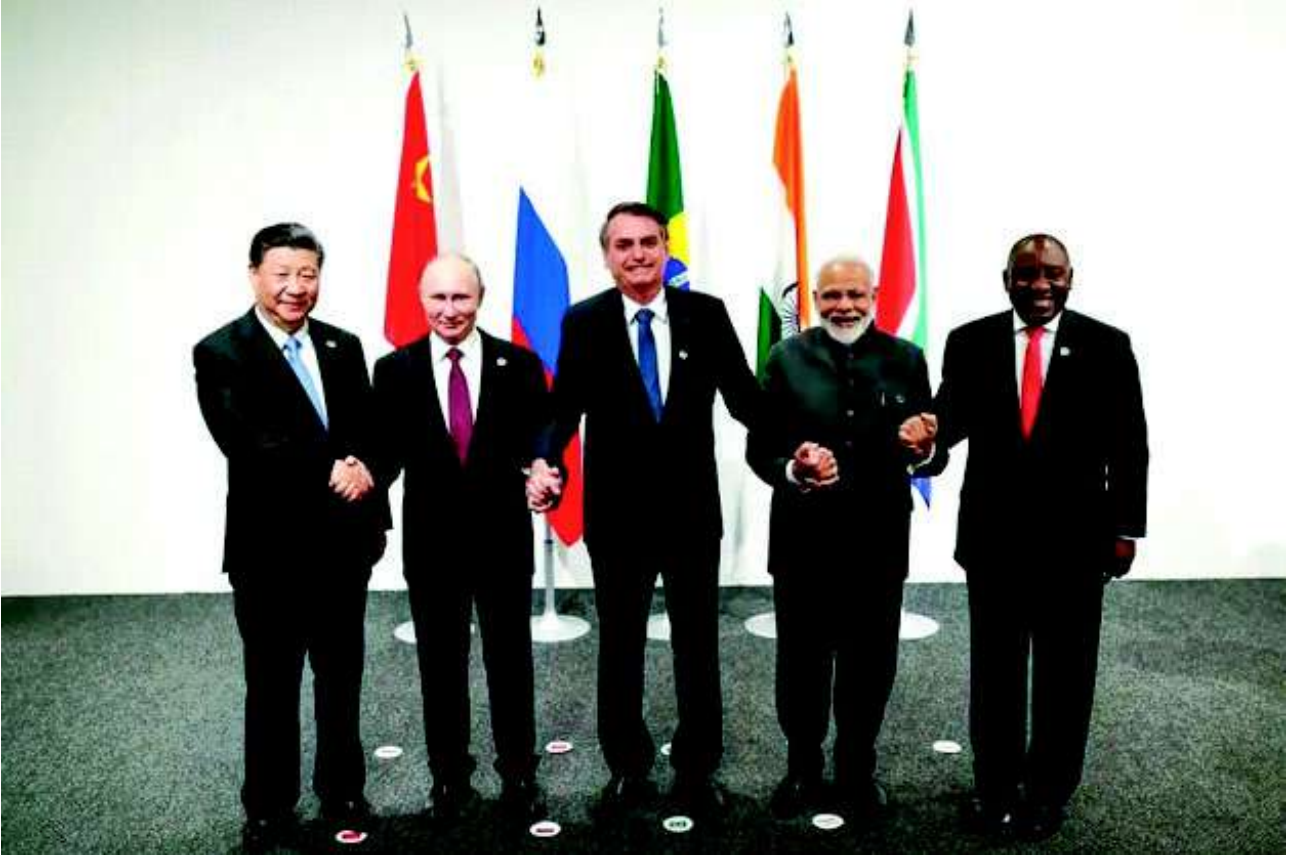
मारना व अफगानिस्तान के तालिबानों को मिटाना था। एक प्रकार से यह मुस्लिम कट्टरपन्थ व मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफ भी वैश्विक हमला था। स्व. नरसिंह राव भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद देश व विदेश में मुस्लिम समाज के निशाने पर थे। सम्भव है कि इसीलिए उन्होंने वेस्ट से हटकर ईस्ट की ओर देखना शुरू किया है। लगभग एक दशक तक भारत की सरकारें इस नीति पर चलती रहीं। परन्तु जब चीनी आर्थिक सत्ता व आर्थिक साम्राज्यवाद से अमेरिका के लिए खतरा शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपनी नीति को बदला। चीन ने अमेरिका

नहीं हो सका है। जिस प्रकार अमेरिका की चीन के प्रति नीति बदलने से भारत भी पूर्व की ओर देखने लगा था उसी प्रकार बाद में अमेरिका की नजर से भारत ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया। इसके लिए कई कई देशों के कई संगठन बनाये जाने शुरू हुए। विदेश नीति में एक बदलाव आया कि विभिन्न विषयों के आधार पर देशों के समूह या संगठन बनाये जायें या जो बने उनमें शामिल हुआ जाए। यह एक प्रकार से दो ध्रुवीय दुनिया के विखंडन की शुरुआत थी। संघाई सहयोग के नाम से एससीओ नामक एक समूह बना जिसमें चीन नहीं था पर पाकिस्तान है। इस संगठन के सम्मेलन में

यद्यपि हम समाजवादियों ने यह माना कि यह डॉ. लोहिया के भारत-पाक महासंघ के द्वारा गरीब व भारत के विभाजन की काली रेखा को कमजोर करने और आक्रामक चीन के मुकाबले एक ताकतवर मंच बनाने की भूमिका से हटने की शुरुआत है। जबकि सार्क के इस विचार ने दक्षिण एशियाई भूभाग में एक एकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया था। हम लोगों ने दक्षिण देशों का सम्मलेन दिल्ली में आयोजित कर सार्क सिटीजन फोरम का गठन किया व उसके लिए काम शुरू किया था।

के के उपभोक्ता बाजार पर कब्जा जमा लिया था। अपनी साहूकारी नीति से पैसा देकर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश आदि देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और वन बेल्ट वन रोड की महत्वाकांक्षी योजना से अपने व्यापार को सड़क मार्ग से ईरान और यूरोप तक जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया था। इस खतरे को समझ कर अमेरिका ने अपने बाजार व सहयोगी देशों के बाजार में चीन को प्रतिबंधित करना शुरू किया। चीनी विस्तार को फिर से रोकने की नीति शुरू की। भारत कभी भी अमेरिकी प्रभाव से मुक्त

हिस्सेदारी करने के लिए 9 वर्षों के बाद भारत के विदेशमंत्री जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचे। यद्यपि यह शिरकत अभी बहुत प्रारंभिक है। इसके चार दिन पूर्व याने 11 अक्टूबर 2024 को वियतनाम में एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सर्वाधिक नाकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। भारत सरकार ने 1950 की निर्गुट नीति, फिर सार्क संगठन फिर, लुक टू द ईस्ट, फिर ब्रिक्स और अब दक्षिण एशिया के आगे जाकर दक्षिणी विश्व



की चर्चा शुरू की है।

ब्रिक्स में भार, रूस, चीन और विश्व के दक्षिण के देश जिनमें साउथ अफ्रीका, किर्गिजस्तान आदि शामिल हैं को महत्व देना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में पश्चिमी एशिया में शान्ति बहाल हो इसकी भी चर्चा शुरू की। याने विदेश नीति का केंद्र अब सार्क से हटकर कुछ पूर्वी एशिया के देशों की तरफदेखना शुरूकिया। ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और ओसानिया के गरीब और पिछड़े देशों के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति अस्थिरता और भटकाव में घूमती है। जिसे अपने वास्तविक राष्ट्रीय हितों की या तो ठीक समझ नहीं है या फिर उनके प्रति गंभीर नहीं है।

पूर्वी एशिया के शिखर सम्मलेन के एक दिन पहले ही नरेन्द्र मोदी ने लाओस में भारत आशियान ने बैठक को सम्बोधित किया था। उपर्युक्त घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति तात्कालिकता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। 1950 के दशक में ही समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने एशियाई समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने रंगून के सम्मलेन में एशियाई समाजवाद की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। वे चाहते थे कि एशिया के सभी देश समाजवाद के रास्ते को स्वीकार करें और एक सामूहिक नीति तैयार करें, जो अमेरिकी पूँजीवाद और नाटो के सैन्य वर्चस्व तथा रूस के साम्यवाद और सेंटो के वर्चस्व से हटकर हो। एशिया के देश राष्ट्रीय सम्पन्नता,

लोकतंत्र, समता और छोटी मशीन के आधार पर एशिया को समाजवादी बनाने की पहल करें। यह पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों के आर्थिक और राजनैतिक वर्चस्व का विकल्प बने। अगर डॉ. लोहिया की विदेश नीति को तत्कालीन भारत सरकार ने स्वीकार किया होता और एशिया में समाजवाद की नीति को स्वीकार किया होता तो भारत की विदेश नीति में स्पष्टता और स्थिरता होती। एशिया अगर आज भी समाज की विचार व्यवस्था और सिद्धांतों पर एक गुट हो सके तो अफ्रीकी महाद्वीप व लेटिन अमेरिकी देश एशिया के साथ होंगे। क्योंकि वे भी पूँजीवादी अमेरिका और यूरोप से शोषित हैं। शोषण मुक्त समाज की दुनिया के लिये यह एक ऐतिहासिक पहल हो सकती है।

छत्तीसगढ़ के पितामह थे सेठ शिवदास डागा

विजया पाठक

सेठ शिवदास डागा का जन्म 22 नवम्बर, 1885 को राजस्थान के बीकानेर नगर में हुआ था। इनके पितामह व्यवसाय के लिए राजस्थान से रायपुर आये।

इनकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के शासकीय हाईस्कूल में हुई। उनकी कार्यशैली इतनी मनमोहक थी कि शीघ्र ही उन्हें लोकप्रियता प्राप्त होने लगी। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सन् 1920 में आनरेरी मजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित किया।

सन् 1920 में महात्मा गांधी का आगमन रायपुर में पहली बार हुआ तथा डागा जी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। गांधीजी के आह्वान पर उन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया एवं पूरे जोश से आंदोलन में सक्रिय हो गये। इस क्षेत्र में रविशंकर शुक्ल एवं डागा जी ने आंदोलन की बांगडोर अपने हाथों में ली तथा सभी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट लोगों को जोड़कर आंदोलन का स्वरूप बढ़ाने के कार्य में लग गए। सन् 1923 में उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर जेल में रखा गया। उनके प्रभाव से एवं गिरफ्तारी के विरोध में पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह का निर्माण हुआ तथा लोग जेल के सामने उनके रिहाई के लिए धरना देना शुरू कर दिया। अतः उन्हें



**सेठ शिवदास डागा का जन्म
22 नवम्बर, 1885 को
राजस्थान के बीकानेर नगर
में हुआ था। इनके पितामह
व्यवसाय के लिए राजस्थान
से रायपुर आये।**

स्थानांतरित कर जबलपुर जेल भेजा गया। जेल से छूटने के बाद तो उनका उग्र रूप अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ता गया।

सन् 1926 में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति एकांत निष्ठा के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने उन्हें मेम्बर आफ लेजिसलेटिव असेम्बली(सेन्ट्रल) के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। उसी



समय कांग्रेस लगभग विभाजित ही हो गई थी। देश के बड़े-बड़े नेता पं. मोतीलाल नेहरू से लेकर पं. मदनमोहन मालवीय तक कांग्रेस छोड़कर स्वराज्य पार्टी बना चुके थे। गांधीजी अपने सिद्धांतों के कारण अकेले पड़ गए थे। हर क्षेत्र के बड़े नेता गांधीजी को छोड़ चुके थे। कांग्रेस और गांधी दोनों के सिद्धांत की रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया था। तब दूसरी पंक्ति के नेताओं ने कांग्रेस की रक्षा का बीड़ा उठाया। उन्हीं नेताओं में सेठ शिवदास डागा भी थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी यही स्थिति निर्मित हो गई। यहां भी क्षेत्र के नेता पं. रविशंकर शुक्ल कांग्रेस छोड़कर स्वराज्य पार्टी से विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए। तब उनके खिलाफ कांग्रेस की ओर से सशक्त उम्मीदवार की खोज होने लगी। नेताओं की कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी। वे प्रभावशाली भी थे, पर शुक्लजी से टकराने को कोई नेता तैयार नहीं था। क्योंकि जीत

सुनिश्चित नहीं थी। उस समय चुनाव लड़ने की वही तैयार हो सकता था जिसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सिद्धांतों की प्रतिनिष्ठा हो। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब डागाजी ही सिद्धांत के लिए अपने मित्र के खिलाफ भी टकराने को तैयार हो गए। डागाजी के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया गया और अंततः जीत डागाजी की हुई। इस जीत ने अखिल भारतीय स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा ने अपनी अलग पहचान बना ली।

सन् 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर सिवनी जेल में रखा गया।

सन् 1933 में गांधीजी का रायपुर में दूसरी बार आगमन हुआ उस समय डागाजी के पास फोर्ड कार थी जिसमें गांधीजी ने पूरे क्षेत्र में दौरा किया तथा वे स्वयं उनके साथ रहे। जब भी रायपुर में किसी भी बड़े नेता का आगमन होता था तो उसकी सारी व्यवस्था का भार डागाजी ही उठाते थे तथा एक समय का भोजन उनके निवास पर

आयोजित होता था। पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पं. गोविन्द वल्लभ पंत, डॉ. अणे, आसिफ अली आदि सभी नेताओं की आगवानी डागाजी के द्वारा की जाती थी।

सन् 1935 में गिरफ्तार कर दमोह जेल में भेजा गया। उसी समय उनके पिताजी के देहावसान की दुःखद सूचना उन्हें दी गई तथा अंग्रेजी हुकूमत से उन्हें पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश की किन्तु उन्होंने इस सिफारिश का ठुकरा दिया तथा जेल में ही रहे।

सन् 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ जिसमें उन्हें उप स्वागताध्यक्ष बनाया गया।

सन् 1942 में गांधीजी द्वारा बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया जिसमें डागाजी, शुक्ल जी आदि लोगों ने भाग लिया। इन्हें पूरे क्षेत्र में अग्रणी होकर आंदोलन को विराट

स्वरूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके प्रभाव की अंग्रेजी शासन को जानकारी थी ही अतः रास्ते में मलकापुर स्टेशन पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा नागपुर जेल में रखा गया। नागपुर जेल से छूटकर आने के बाद आंदोलन को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की प्रक्रिया में थे। जगह-जगह सभाओं का आयोजन कर क्षेत्र में स्वतंत्रता का बिगुल बजाना शुरू किया।

सन् 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा बेल्लूर जेल भेजा गया। यहां उन्हें उनकी पुत्री की अस्वस्थता का समाचार प्राप्त हुआ। उनकी पुत्री तपेदिक की बीमारी के इलाज के लिए त्रिजनापल्ली अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें पैरोल में छोड़ा गया तथा अपनी पुत्री के अंतिम क्षण में उसके पास पहुंचे तथा कुछ क्षण बाद ही उनकी पुत्री ने अंतिम सांस ली। एक तपे हुए सैनिक की भांति उन्होंने यह सदमा बर्दास्त किया तथा पैरोल की अवधि समाप्त के पूर्व ही उन्होंने अपने आप को सरकार के सुपुर्द कर दिया। इस बीच उनकी ख्याति छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन् पूरे देश भर में पहुंच चुकी थी। देश के सभी प्रमुख नेताओं से उनका संपर्क बढ़ता ही गया।

महात्मा गांधी के सानिध्य के प्रभाव से उन्होंने रायपुर में हरिजन छात्रावास की स्थापना की। उस समय बालिकाओं की शिक्षा नहीं के बराबर थी। अतः बालिकाओं की शिक्षा की ओर प्रेरित करने हेतु आरंग में अपनी पत्नी श्रीमती छोटीबाई डागा के नाम से शाला की स्थापना की।

अपने सहयोगी पं.रविशंकर शुक्ल के साथ मिलकर रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय एवं बाल आश्रम की स्थापना की तथा भवन निर्माण कराया। यही राष्ट्रीय विद्यालय अंग्रेजों के खिलाफ सूत्रपात का केन्द्र बना। इसी विद्यालय के अंतर्गत आज हायर सेकेंडरी स्कूल, डागा कन्या विद्यालय संचालित है।

जगत विजन

सेठ शिवदास डागा सन् 1938 से 1945 तक लगातार रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। रायपुर में कांग्रेस का कार्यालय उनका व्यवसायिक स्थल हरीबाड़ा ही हुआ करता था। उस समय कांग्रेस कमेटी का भवन नहीं था। डागाजी ने अपनी करीब 20 हजार वर्ग फीट भूमि कांग्रेस भवन निर्माण हेतु दान दी तथा अपने नेतृत्व में कांग्रेस भवन का निर्माण कराया। कांग्रेस भवन के निर्माण की लागत का बड़ा हिस्सा डागाजी ने वहन किया। इस तरह कांग्रेस की सेवा जो डागाजी ने की है उसकी दूसरी मिसाल मिलना असंभव है।

सेठ शिवदास डागा सन् 1938 से 1945 तक लगातार रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। रायपुर में कांग्रेस का कार्यालय उनका व्यवसायिक स्थल हरीबाड़ा ही हुआ करता था। उस समय कांग्रेस कमेटी का भवन नहीं था। डागाजी ने अपनी करीब 20 हजार वर्ग फीट भूमि कांग्रेस भवन निर्माण हेतु दान दी तथा अपने नेतृत्व में कांग्रेस भवन का निर्माण कराया। कांग्रेस भवन के निर्माण की लागत का बड़ा हिस्सा डागाजी ने वहन किया। इस तरह कांग्रेस की सेवा जो डागाजी ने की है उसकी दूसरी मिसाल मिलना असंभव है।

सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया जिसमें अखिल भारतीय स्तर के 48 सदस्यों का चयन हुआ जिसका अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उक्त समिति में डागाजी का भी मनोनयन हुआ। संविधान में मताधिकार के लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने महिला एवं पुरुष दोनों की आयु 21 वर्ष करने की सुझाव

दिया। डागाजी ने पुरुष की आयु 21 वर्ष एवं महिलाओं की आयु 18 वर्ष करने का सुझाव दिया जिसे वल्लभभाई पटेल एवं भोलाभाई देसाई ने सहमती जताई और संविधान निर्माण समिति ने मान्य किया। उनके अत्यंत स्पष्ट एवं निर्भीक विचारों के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ केसरी की उपाधि दी गई थी।

सन् 1952 में प्रथम लोकसभा के चुनाव में उन्हें महासमुन्द सरायपाली क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। राजिम में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वापसी के दौरान उन्हें पक्षाघात(लकवा) हुआ। इसके कारण अपने चुनाव प्रचार में नहीं जा पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 1 लाख 80 हजार वोटों से परास्त कर निर्वाचित घोषित किये गये।

उनकी तबीयत में निरंतर सुधार तो हुआ किन्तु 6 माह बाद अचानक अस्वस्थता के दौरान 10 जून 1952 को उनका स्वर्गवास हो गया।

भोपाल, दिसम्बर-2024

Maharashtra Assembly Elections: OBCs teach Jarange's patron Sharad Pawar a lesson

Shrawan Deore

Former Congress chief minister of Maharashtra, Prithviraj Chavan, was the first to polarize the Marathas against the OBCs. Later, in 2016-17, Devendra Fadnavis did the same to benefit the BJP. However, Fadnavis managed to keep the Marathas in check. Hundreds of thousands of people took part in demonstrations, there was fear in the air, but such a situation wasn't allowed to take a violent turn. But

the OBCs still gave a big jolt to Fadnavis in the 2019 elections. That was because his government had a Bill granting reservations to the Marathas passed in the Assembly. Fadnavis lost 17 seats, his chief ministership and his party was unseated from the government. He drew the right lessons, did away with his pro-Maratha stance and came out with a new slogan to please the OBCs. He declared that the OBCs were a part of the

BJP's DNA.

In 2022, Fadnavis engineered the fall of the Maha Vikas Aghadi (MVA) government led by Uddhav Thackeray and a new government led by Eknath Shinde came to power. Sharad Pawar crafted the Jarange factor to hijack the Maratha reservation issue. Jarange was made to observe hunger strikes at Vadi-Godri and Aantarvali Sarati. Initially, Manoj Jarange could not garner much support and the





protest. The media ignored it completely mainly because it was democratic and peaceful. There was no vandalism, no violence. How would it raise TRP? No media means no publicity. Hence Dalit and progressive leaders, too, did not visit the venue of the protest in Chandrapur.

Jarange took a dig at the Dalit, OBC, progressive and left-wing leaders, who had joined him in his hunger strike. Jarange said, "The Dalit, Adivasi and OBC people are worthless. But because they get reservations, we Marathas of 96 clans, we the superior people, have to work under these nincompoops. This is a matter of great shame for the Marathas." The Dalit, OBC and progressive leaders, who had gone to support Jarange, readily accepted this abject insult, proving how thick-skinned they were.

Be that as it may, this was followed by Sharad Pawar's visit to the constituencies of Chhagan Bhujbal and Dhananjay Munde, where he delivered anti-OBC speeches, upping the ante this when no elections were due in these constituencies. All this encouraged Jarange. His supporters reduced to ashes a grand hotel worth Rs 8 crore owned by Samta Parishad leader Subhash Raut in Beed. OBC MLA Sandeep Kshirsagar's house was set on fire, which would have burnt his wife, children and elderly parents alive had it not been for a Muslim neighbour who risked his life, entered the burning house and saved them. In the Madha constituency, homes of Nai (OBC) families in Tulsi village were burnt

media, too, ignored him. But as Sharad Pawar's Nationalist Congress Party (NCP) began propping him up, his hunger strikes began getting more prominence.

As the hunger strike continued, Fadnavis, who was the deputy chief minister and the home minister, tried to use the police to end the protest. Sharad Pawar, even when he is not in power, has a hold on the administration. He made his men join the protest and ensured a clash with the cops.

After this clash, the people present at the strike venue dispersed and Jarange ended his hunger strike. But Rajesh Tope, appointed by Pawar to oversee the Jarange factor, drove to Jarange's residence and persuaded him to relaunch his hunger strike. Tope used his party's network for backing Jarange.

The violence and the tension

in the air was generating lots of stories for the media and Jarange's hunger strike came as a godsend. To boost TRP, the strike was given a lot of publicity. This got into Jarange's head. He began hurling expletives at the OBC leaders. He used absolutely indecent language to insult Fadnavis and chief minister Shinde. "Bury them, pull them down, crush them, teach them a lesson" Jarange kept on vomiting these kinds of phrases day in, day out.

On the day Jarange began his fast in Aantarvali Sarati, OBC leader Ravindra Tonge began his fast too in Chandrapur. But in Chandrapur, the presence of media personnel, politicians and government servants at Tonge's event was meagre. The Dalit, OBC and progressive-leftwing leaders, who sat at the feet of Jarange to extend their support to the agitation, did not care to visit Chandrapur to back the OBC



down. Men and women were mercilessly thrashed. To strike terror in the hearts of the OBCs, hair-cutting salons of the members of the Nai community were vandalized in Gangamasla village of Majalgaon tehsil in Pankaja Munde's constituency. In Beed town, Shubham Jewellers, a shop owned by the Lolge family of the Sunar (OBC) caste, was set afire.

Reports of abusing and attacking throwing ink on doctors, professors and other intellectuals, who supported reservations for the OBCs or opposed Jarange through their posts on social media, began pouring in from village after village. Educational institutions owned by the Marathas sacked some OBC professors. This terrorized not only OBC activists

but also ordinary OBC people.

The clouds of fear dissipated with Chhagan Bhujbal organizing a mega 'Kranti Sabha' of the OBCs at Ambad on 17 November 2023. The OBCs heaved a sigh of relief. For this, Bhujbal had to resign from the council of ministers. However, in view of the popular support Bhujbal enjoyed and given his aggressive posturing, neither Chief Minister Shinde nor the two Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar could gather the courage to accept his resignation.

Every informed person knows that it was Sharad Pawar who polarized the Marathas against the OBCs. In the 2024 Assembly elections, safety in the face of Maratha aggression was the key issue before the OBCs. Needless to say, had MVA come to power, its

government would have been under the thumb of Sharad Pawar. When Sharad Pawar, without being in power, could use the Jarange factor to whip up violence, with the government under his control, he could have done much more. The OBCs felt that Pawar's backing would make the Jarange factor even more violent and that caste violence along the lines of Manipur and Haryana in the state would lead to an existential crisis for the community. That is the reason the first priority of the OBCs was to give a sound drubbing to the Sharad Pawar-led MVA in the polls and hand over power to the BJP-led Mahayuti. Their second priority was to ensure that Fadnavis became chief minister. The OBCs felt that with Fadnavis at the helm, they would be safe



because even as home minister he had tried to curb the Jarange factor. That was the reason Jarange had branded him as a villain for the Marathas. So, as per the formulation that “even a Brahmin is preferable to a Maratha”, the OBCs were keen to see Fadnavis occupy the chief minister's post. This made them vote for even the Maratha candidates of the BJP and ensure victories with huge margins for the Maratha parties in the Maha Yuti Shinde's Shiv Sena and Ajeet Pawar's NCP. They were well aware that the BJP would come to power only if the Maha Yuti won a majority; that an OBC tsunami in favour of the BJP would weaken Shinde's claim to chief ministership and Fadnavis would head the new government.

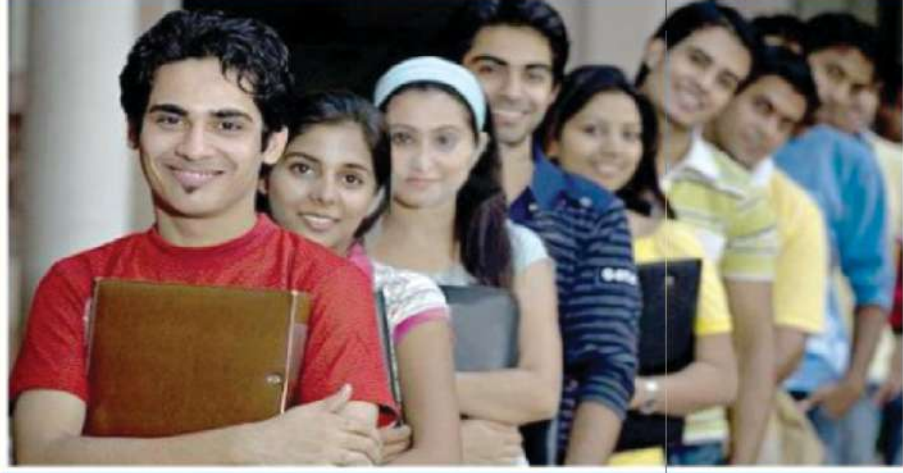
Thus, unlike Jarange, the OBCs did not turn completely hostile against any particular caste. In fact, the OBCs even rejected the OBC candidates fielded by Vanchit Bahujan Aghadi because had they won, they would have taken orders from Prakash Ambedkar, who has been a firm supporter of Jarange from Day One and still is.

During the campaign for the elections, Prakash Ambedkar did make some perfunctory statements backing the OBCs. But the OBCs knew that once elections were done with, he would side with Jarange against them. How could the OBCs forget that Prakash Ambedkar had openly backed Jarange on the 'Sage-Soyre' (that Marathas should be given reservation within

the OBC quota and not separately) issue? No wonder most of the Vanchit Bahujan Aghadi candidates ended up forfeiting their deposits in the elections. The OBC voters have taught all leaders who backed Jarange a lesson they won't forget in their lifetime.

Most of the journalists, scholars and politicians analyzing the defeat of MVA and the victory of Maha Yuti are focusing on inconsequential issues like EVMs, the Ladli-Behna scheme and distribution of cash. I will deliberate on the tug of war between the different constituent parties of the Maha Yuti in the formation of the government, the real reasons behind it and the next step of the OBCs in the fourth part of my analysis.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.